₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

नवम्बर 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

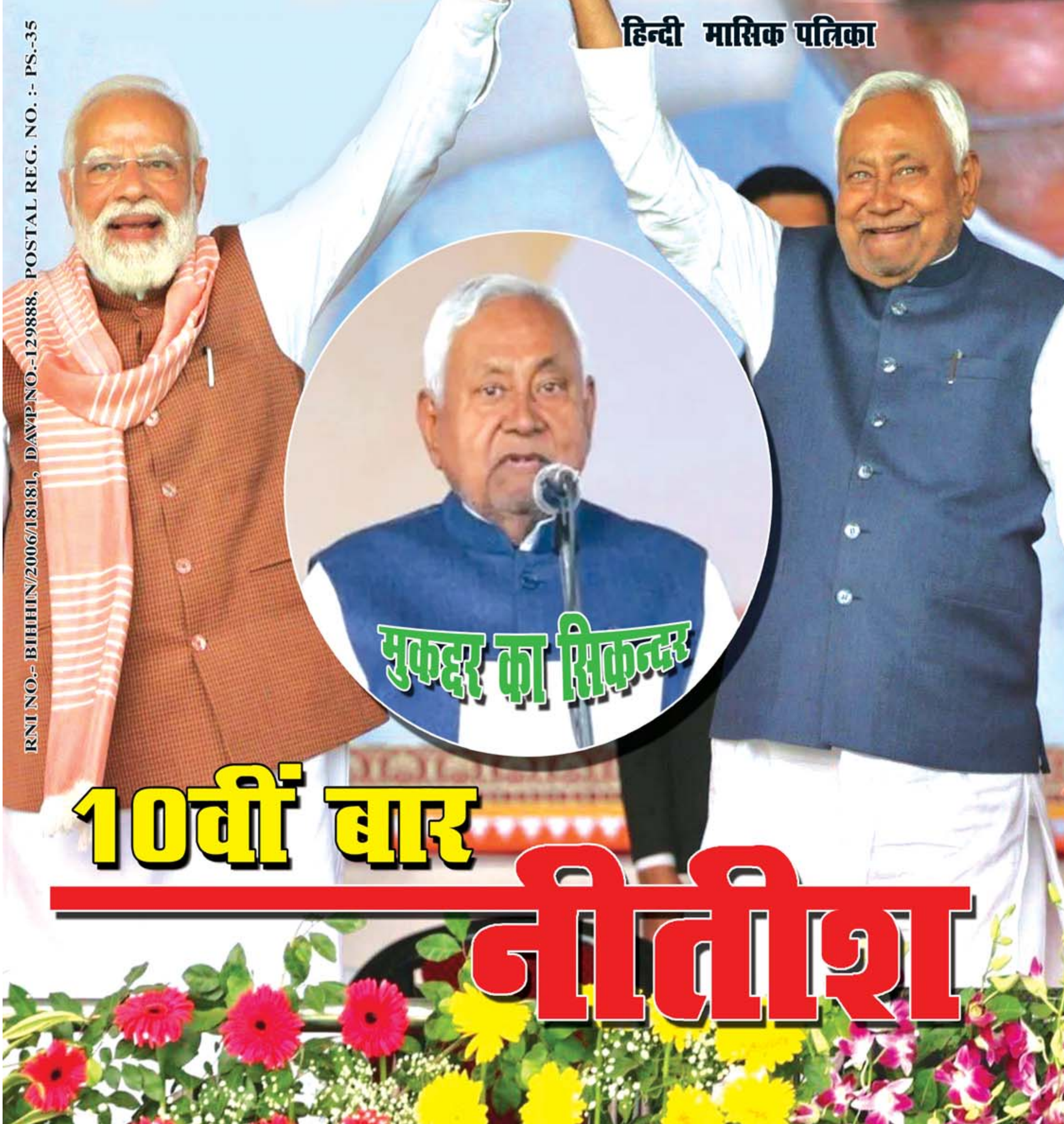

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008

समृद्ध बिहार

खुशहाल बिहार

बिहार उन्नति, समृद्धि एवं विकास के पथ पर निरंतर बढ़ते रहे

इन्ही शुभकामनाओं के साथ

10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार जी को एवं

उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी को

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

की ओर से हार्दिक बधाई।

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

बिहार में विकास 2005 के बाद देखने को मिल रहा है इस बात को नकारना गैरमुनासिब होगा। 20 वर्षों बाद बिहार आने वाले यात्री या बिहारी को 8वां अजूबा से कम नहीं लगेगा क्योंकि मरिन ड्राइव और मेट्रो पटना में होगा सच साबित हो रहा है। सूबे के सभी 38 जिलों में विकास जातिवाद पर हावि होता दिख रहा है क्योंकि केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर प्रदेश की 12 करोड़ आबादी को वह सबकुछ देना चाहती है जिसकी जरूरत 20 साल पहले थी लेकिन विकास की गति के साथ-साथ बिहार में भ्रष्टाचार भी उसी गति से बढ़ा जिस गति से विकास अपनी पटकथा लिख रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास-विकास हो रहा है लेकिन बिहार की राजनीति में आज भी विकास पर जातिवाद हावि दिख रहा है। किसी भी पद पर विराजमान राजनेता अपनी जाति की औकात दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन हर जाति की के सर्वमान्य नेता कोई एक हो ऐसा बिहार में नहीं दिखता। नीतीश कुमार की जाति को छोड़ दें तो सभी जाति में थोक भाव में नेता हैं और विभिन्न दलों में अपनी उपस्थिति को कायम किये हैं। माय समीकरण में भी दरार पड़ चुका हैं और मा, य के साथ ही रहे यह दावे के साथ राजद चुनाव नहीं जीत सकता। जातिवाद एवं धर्म आज भी विकास की गति पर ब्रेक लगा सकता है, इसलिए विपक्ष माय को किसी भी सूरत में साथ रखना चाहता है अन्यथा सरकार बनाना मुश्किल है।

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

जातिवाद या विकास से बढ़ेगा बिहार

वोट चोरी को लेकर बिहार में इंडी गठबंधन यात्रा पर निकाल कर बिहार की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वोटर पर कोई विशेष प्रभाव होता नहीं दिख रहा है क्योकि जिनका नाम कटा है वह खुलकर चुनाव आयोग का विरोध नहीं कर पा रहे हैं आयोग सिर्फ खानापूर्ति के अलावा कुछ खास करता नहीं दिख रहा है। आजकल विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों का फर्जी उम्र प्रमाण-पत्र का आरोप लगाकर जन्मतिथि का शपथ-पत्र भी जारी कर रहे हैं इससे तो साफ हो जाता है कि आयोग गहनता पूर्वक दस्तावेजो की जांच नहीं करता है। 1990 से 2005 तक लालू-राबड़ी की सरकार पर जंगलराज, जातिवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते विपक्षी नहीं थकते थे और 2005 से 2025 तक एनडीए की सरकार (05 साल महागठबंधन की सरकार) की सरकार में भी विपक्षी महाजंगलराज, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अफसरवाद का गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूकते। यह भी सच है कि 15 साल बनाम 15 साल की सरकार के क्रिया-कलाप पर समीक्षा होगी तो नीतीश कुमार की सरकार को 100 में 80 नंबर देने से बिहार की जनता पीछे नहीं हटेगी क्योकि जातिवाद के बढ़ते प्रभाव के साथ विकास की रफ्तार भी प्रदेशहित में हुआ है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो या पुल-पुलिया, सरकारी भवन हो या पुलिस थाना, किसान हो या व्यापारी विकास की गति से कहीं न कहीं संतुष्ट होते दिख रहे हैं और सविंदा पर हो रही नियुक्ति ने शिक्षित लोगों का पलायन रोकने में कामयाब भी हुइ है लेकिन कल-कारखानों को खोलने की उपस्थिति से लोग निराश ही दिख रहे हैं। 21वीं सदी में चंद मिनटों में संवाद को शहर से गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब राजनीतिक पार्टियों को आज भी विकास से हीं ज्यादा अपनी जाति एवं धर्म के दम पर ही चुनाव जीतने का विश्लेषण करते हैं। 243 बिहार विधानसभा सीट में अनुसूचित जाति के 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें सुरक्षित है और शेष के सीटों पर जातिय समीकरण बैठाये बगैर कोई भी दल अपना उम्मीदवार नहीं बनाता। विकास पर जातिवाद इस कदर हावि है कि प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र की सरकार भी जातीय जनगणना करवा रही है ताकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में गठबंधान का गणित जातिय समीकाण के दृष्टिकोण से बनाया जा सके। पुल गिर जाता है, हॉस्पीटल में सही ईलाज नहीं होता, विद्यालय में स्तरीय शिक्षा नहीं मिल रहा है, मोटेशन के नाम पर जमकर वसूली हो रही है, टेंडर में जमकर दलाली का महादौर चल रहा है, उसपर विपक्ष मुखर होने के बजाय आज भी माय समीकरण का ही खेल से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बाजी अपनी पक्ष में करना चाहता है वहीं नीतीश कुमार जाति के दृष्टिकोण से अल्पमत में हैं लेकिन जुगाड़ राजनीति में चाणक्य की भूमिका अदा करते हुए 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिपके हुए हैं और दोनों मजबूत दलों के पास उनका कोई विकल्प नहीं दिखता है। प्रदेश में यादव, पासवान, चमार, कुशवाहा और ब्राह्मण ऐसी जातियां हैं जो बिहार की राजनीति की दिशा को तय करते हैं। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट 2023 से पता चला है कि ओबीसी (27.13%) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप-समूह (36%) राज्य की कुल 13.07 करोड़ की आबादी का 63% हिस्सा है, जबकि एससी और एसटी कुल मिलाकर 21% से थोड़ा अधिक हैं। भूमिहारों-राजपूतों और ब्राह्मणों को सत्ता से दूर करने में दलितों और पिछड़ों की बड़ी भागीदारी थी। कर्पूरी ठाकुर दलित और पिछड़े समाज की आवाज बन रहे थे। और धीरे-धीरे बिहार में सत्ता की कहानी जो भूमिहारों से शुरू हुई थी, वह राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और पिछड़ों के बाद दलितों के हाथ में जा चुकी थी। बिहार में जातिगत सत्ता-स्थानांतरण की मुख्य वजह थी दलितों और पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता और सत्ताहीन सवर्णों की छटपटाहट। यहीं से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया था प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका बार-बार उल्लेख मिलता है। चार वर्ग है जिसमें ब्राह्मण (पुरोहित वर्ग), क्षत्रिय (शासक, प्रशासक और योद्धा; जिन्हें राजन्य भी कहा जाता है), वैश्य (कारीगर, व्यापारी और किसान) और शूद्र (मजदूर वर्ग)। बिहार की अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर हुई 5.31 लाख करोड़ की, राज्य की विकास दर 8.64 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 8.64 प्रतिशत रही। बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के आधार पर अपना वोट दिया और जाति, वर्ग की राजनीति को नकार दिया। 2010 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव था। जातिवाद और विकास एक-दूसरे के घोर विरोधी हैं, क्योंकि जातिवाद भेदभाव और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज के एक बड़े हिस्से की क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और राष्ट्र का समग्र विकास अवरुद्ध होता है। जातिगत व्यवस्था संसाधनों के अनुचित आवंटन, उद्यमिता में कमी और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देती है, जबकि विकास के लिए प्रतिभा, योग्यता और सभी नागरिकों के समान अवसरों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तमाम विकास के दावों के बीच जातिवाद का ही परचम लहरता दिख रहा है और सभी गठबंधन अपने उम्मीदवारों की जाति एवं दबंग और धनवान लोगों की खोजने में जुट चुकी है और जातिवाद ही जितेगा यह तय हो चुका है। विकास की रफ्तार पर जातिवाद आज भी हावि दिख रहा है।

अक्टूबर 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

हमारा पता है :- द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

ध्यान

ब्रजेश जी,

केवल सच, पत्रिका के अक्टूबर 2025 अंक में शोधार्थी रणधीर कुमार सिंह ने अपने आलेख ''**ध्यान के अभ्यास से मिलेगा स्वस्थ जीवन**'' में योग के महत्व को पूरी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है और यह बताने की सफल कोशिश किया है कि ध्यान से कई प्रकार की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। योग, ध्यान और अध्यात्म के महत्व को पूरा विश्व स्वीकार करता है। इस प्रकार की खबरें सही मायने में समाज के बीच आना चाहिए ताकि सकारात्मक विषयों से आवाम को लाभ पहुंचे।

✦ रामपाल प्रसाद वर्मा, राजा बाजार, पटना

संपादकीय एवं दवा उद्योग

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय सच में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। अक्टूबर 2025 अंक में प्रकाशित संपादकीय ''गठबंधन से धर्मसंकट में वोटर'' सटीक समीक्षात्मक लगा। वही शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबर ''दवा उद्योग का बंटाधार'' आलेख में बिहार में चल रही सरकारी विभाग के द्वारा दवा को लेकर भ्रष्टाचार एवं राजनीति चरम पर पहुंच चुका है। पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की काली करतूत को उजागर कर रहे हैं, जो काबिले तारिफ है। यह दोनों सही खबरें लगी।

✦ प्रभुदयाल सक्सेना, गाँधी नगर, नई दिल्ली

आरंभ है प्रचंड

मिश्रा जी,

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित एवं स्थायी पाठक हूं। अक्टूबर 2025 अंक में अमित कुमार की आवरण कथा ''**सियासत का महासंग्राम, आरंभ है प्रचंड...!**'' में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी पठनीय एवं संग्रहनीय खबर को प्राथमिकता के साथ समीक्षात्मक ढ़ंग से लिखा है। राजनीति के विभिन्न पहलुओं सहित प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी टिकट बंटवारे के साथ चुनाव के मुद्दे को गंभीरता के साथ पाठकों के समक्ष रखा है और इस प्रकार की खबरें लोगों को काफी प्रभावित करती हैं। आपकी पत्रिका केवल सच, सच को महत्व देती है।

✦ एच. के. राठौर, अचुवाड़ा, बाढ़, पटना

एक पर एक झारखंड

मिश्रा जी,

झारखंड की खबरों को केवल सच, पत्रिका स्थान देने लगा है जिसमें भारती मिश्र, ओम प्रकाश एवं गुड्डी साव की खबरों को पढ़कर सटीक जानकारी मिलती है। चर्चित खबरें ''पुलिस और राहुल दूबे गिरोह के बीच जर्बदस्त मुठभेड़'', ''झारखंड का महासंग्राम अस्तित्व और कुर्मी पहचान की लड़ाई'', ''संवाद, विश्वास और नई सोच का संगम'', ''युवती की हत्या, पिता-पुत्र गिरफ्तार'' जैसी अन्य कई खबरें है जो पठनीय है। मैं राँची में रहता हूं लेकिन मुंगेर जिला का निवासी हूं और इस पत्रिका का नियमित पाठक हूं। इसकी खबरें बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ लिखा जाता है।

✦ कौशलेन्द्र सिंह, टावर चौक मुंगेर, बिहार

चुनावी मुद्दा

संपादक जी,

अक्टूबर 2025 अंक में पत्रकार अजय कुमार की खबर ''**रायबरेली से सुप्रीम कोर्ट तक**'' में कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न को बनाया बड़ा चुनावी मुद्दा को पढ़कर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ जातिगत राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाती है। दूसरी खबर ''योगी की तारिफ से क्यों बढ़ीं अखिलेश की बेचैनी'' में भी समाजवादी के भीतर के अंर्तकलह को भी उजागर करते हुए लिखा है। इस अंक की सभी खबरें एक पर एक है। अगर यह पत्रिका रंगीन पृष्ठों पर प्रकाशित हो तो इसके पाठकों की संख्या में भी काफी वृद्धि होगी।

✦ अभिषेक राय, 104, हाउसिंग कॉलोनी, राँची

दिल्ली की खबरें

संपादक जी,

संजय कुमार सिन्हा की अक्टूबर 2025 अंक में प्रकाशित खबर ''दिल्ली के लालकिला मैदान में विश्व प्रसिद्ध लव-कुश रामलीला का हुआ भव्य आयोजन'' में कार्यक्रम को सही ढ़ंग से नियंत्रण करते हुए खबर को लिखा है। रेखा गुप्ता की सरकार में सनातन धर्म को काफी महत्व मिल रहा है। दुर्गापूजा, दिपावली, छठ्ठ जैसे पर्व को दिल्ली में देखने को मजबूती से मिल रहा है जबकि पिछली सरकार को सिर्फ मुसलामन से सारोकार रह गया था। संजय जी आपकी पिछले कई अंक की खबरों को पढ़ा है। आप संघ एवं धर्म की खबरों को स्थान देते है। बधाई हो।

✦ विश्वजीत सिंह, घंटा घर, नई दिल्ली

अन्दर के पन्नों में

33

35

38

95

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्षः- 20	अंकः- 234	माहः- नवम्बर 2025	मूल्यः- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

अविनाश कुमार 7992258137, 9430985773

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

ऋषिकेश पाण्डेय 7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :- श्रीधर पाण्डेय 9470709185
(म०) :- गौरव कुमार 9472400626
(ग्रा०) :- मुकेश कुमार 9473038020
बाढ़ :-
भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547
बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034
कैमूर :-
रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506
:-
गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916
(ग्रा०) :-
औरंगाबाद :-
जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939
अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543
नालन्दा :-
:-
नवादा :- अमित कुमार 9162664468
:-
मुंगेर :-
लखीसराय :-
शेखपुरा :-
बेगूसराय :-
:-
खगड़िया :-
समस्तीपुर :-
जमुई :- अजय कुमार 09430030594
वैशाली :-
:-
छपरा :-
सिवान :-
:-
गोपालगंज :-
:-
मुजफ्फरपुर :- .
:-
सीतामढ़ी :-
शिवहर :-
बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649
बगहा :-
मोतिहारी :- संजीव रंजन तिवारी 9430915909
दरभंगा :-
:-
मधुबनी :-
:- प्रशांत कुमार गुप्ता 6299028442
सहरसा :-
मधेपुरा :-
सुपौल :-
किशनगंज :-
:-
अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870
पूर्णिया :-
कटिहार :-
भागलपुर, :-
(ग्रा०) :- रवि पाण्डेय 7033040570
नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
.................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

.................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**
☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....
....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

....
....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

बिहार! एक ऐसा प्रदेश जो कभी अपराध की फैक्ट्री कही जाती थी। रात के अंधेरे तो छोड़ीए, दिन के उजाले में ही चिकित्सक, उद्योगपति, व्यापारी फिरौती के लिए उठा लिए जाते थे। 90 का दशक बिहार में अपराध का प्रारंभ माना जाने लगा और सरकार चला रहे थे लालू प्रसाद यादव। जेपी और कर्पूरी के दो शिष्यों-लालू और नीतीश ने बिहार के परिदृश्य को बदलने की पटकथा लिखना प्रारंभ कर दी थी, पर बिहार को चलाने का पहला मौका लालू प्रसाद को ही मिला। उनके ही शासनकाल में आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास का बलात्कार हुआ और फिर हत्या, उनकी ही सरकार में शिप्पी-गौतम जैसे बड़े काण्ड सुर्खियां बंटोरे, उनकी ही सरकार में चारा घोटाले हुए। बेवश जनता दबी जुबान से इस सरकार को कुछ कह पाने में डरती रही, किन्तु न्यायालय ने इसे 'जंगल राज' नाम दिया। बहरहाल, इसी 'जंगल राज' के डर को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार ने राजनीतिक शतरंज पर जीत हासिल करते हुए वर्ष 2005 में सहयोगी भाजपा के साथ सरकार बनायी और लालू-राबड़ी का किला ध्वस्त किया। सरकार बनते ही पहला काम अपराध पर नियंत्रण लगाना था, तो स्पीडी ट्रायल लाकर अपराधियों की गिरफ्तारी और तुरंत फैसले से अपराध पर धीरे-धीरे अंकुश लगने लगे। जनता ने इस नये बिहार का नाम 'सुशासन' दे डाला और नीतीश कुमार बन गये 'सुशासन बाबू'! राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार 2005 के बाद 2010 का भी चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। 16 जून 2013 को, नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने के बाद जेडीयू एनडीए से अलग हो गई, जिसके बाद भाजपा के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़कर 20 सीटों के मुकाबले सिर्फ 2 सीटें जीतीं। कुमार ने चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनाये गये। इसके बाद बिहार की राजनीति बदलती गई और हालात एवं परिस्थितियों के बीच 2015, 2017, 2020, 2022, 2024 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाये गये। 9 बार मुख्यमंत्री के ताज से सुशोभित नीतीश कुमार 2025 में सहयोगी भाजपा सीटों के लिहाज से बड़े भाई होने के बाद भी 20 नवम्बर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाये गये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक बार राजद नेता व बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन ने कहा था की 'नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं'! उनकी ये बाते कितनी सच है यह तो खुद में मंथन का विषय है किन्तु बिहार के विकास और बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश बिहार की जनता के लिए विकल्प नहीं संकल्प हैं, इसे इसबार के चुनाव में भी देखने को मिला। बहरहाल, दस बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि वह 'मुक्कद्दर के सिकंदर' हैं!

बिहार विधानसभा की चुनावी समीक्षा पर प्रस्तुत है संयुक्त संपादक **अमित कुमार** की विशेष रिपोर्ट :-

विधानसभा के 243 सीटों पर दलों को मिली सीटें

एनडीए					
भाजपा- 89	जद यू-85	आरएलएम-19	एचएएम-05	आरएलएम-04	बीएसपी-01

महागठबंधन							
आरजेडी-25	कांग्रेस-06	वीआईपी-00	आईआईपी-01	सीपीआई (एमएल)-02	सीपीएम-01	एआईएमआईएम 05	जन सुराज 00

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद सभी 243 सीटों के नतीजे जारी हो गए। चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के एनडीए को 202 और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 और मायावती की बीएसपी ने 1 सीट जीती है। दोनों गठबंधन के पार्टी की लिस्ट देखें तो एनडीए में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, एचएएम को 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। महागठबंधन में आरजेडी 25, कांग्रेस 6, सीपीआई-एमएल 2, सीपीएम और आईआईपी 1-1 सीट जीती है। अलबत्ता एनडीए की इतनी बड़ी जीत पूरे देश के लिए समीक्षा का विषय बन गई है। बहुमत में आने के बाद एनडीए में सरकार गठन को लेकर मंथन जारी था कि कौन अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा, क्योंकि 89 सीट के साथ भाजपा बड़ी पार्टी बन गई है। सारे मंथन के दौर खत्म होने के बाद एनडीए की बैठक में सभी दलों ने एक साथ नीतीश कुमार को पुन: मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अगले पांच वर्षों तक कार्य करेगी, इसे लेकर बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के साथ ही दो उपमुख्यमंत्री सहित 24 मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए 20 नवंबर का दिन मुक्करर हुआ और ऐतिहासिक गांधी मैदान को इसके लिए स्थान चुना गया।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ ली। बता दें कि नीतीश ने पहली बार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2010, 2015 (दो बार), 2017, 2020, 2022 (दो बार) और 2024 में शपथ ली थी। अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 10वां कार्यकाल शुरू कर दिया है। वह बिहार के अब तक सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल करने का वादा किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, "आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।" उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।' 'मुझे विश्वास है कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम बिहार को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे।" वही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने।

24 विधायकों और एमएलसी को भी राज्यपाल ने पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ

बिहार सरकार के नये कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश

विजय कुमार चौधरी
जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन-संपर्क, भवन निर्माण

बिजेन्द्र प्रसाद यादव
ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर

श्रवण कुमार
ग्रामीण विकास एवं परिवहन

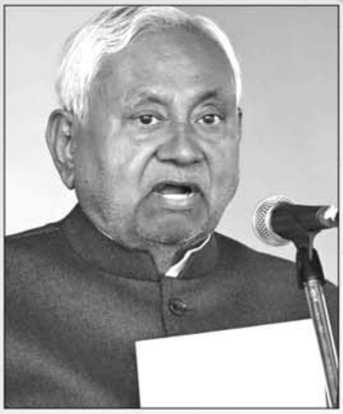

नीतीश कुमार
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन

मंगल पांडे
स्वास्थ्य और विधि विभाग

दिलीप कुमार जायसवाल
उद्योग विभाग

अ

लेसी सिंह
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

नितिन नवीन
पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास

मदन सहनी
समाज कल्याण

सम्राट चौधरी
गृह विभाग

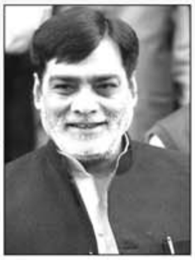

रामकृपाल यादव
कृषि विभाग

संतोष सुमन
लघु जल संसाधन विभाग

स
शिक्षा
ए

मो० जमा खान
अल्पसंख्यक कल्याण

संजय सिंह टाइगर
श्रम संसाधन विभाग

अरुण शंकर प्रसाद
पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग

सुरेंद्र मेहता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

नारायण प्रसाद
आपदा प्रबंधन विभाग

व

लखेंद्र कुमार रौशन
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

श्रेयसी सिंह
सूचना प्रावैधिकी एवं खेल विभाग

डॉ० प्रमोद कुमार
सहकारिता एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग

विजय कुमार सिन्हा
भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूततत्व विभाग

संजय कुमार
गन्ना उद्योग विभाग

संजय कुमार सिंह
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

दी
पंच

ली। लखीसराय से विधायक चुने गए विजय कुमार सिन्हा को भी राज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ज्ञात हो कि दोनों ही दिग्गज नीतीश की पिछली सरकार में भी उपमुख्यमंत्री थे। इनके अलावे विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, डॉ. दिलीप जायसवाल, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने मंत्री के रूप में शपथ ली। लेसी सिंह, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, मदन सहनी और सुनील कुमार को भी महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इनके साथ ही जमा खान नीतीश कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक नेता है। संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण साह और रमा निषाद ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। लखेंद्र कुमार, श्रेयसी सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार, दीपक प्रकाश, संजय कुमार और संजय सिंह को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दीं। शपथ समारोह बीतने के अगले दिन ही विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। दिगर बात यह रही की बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है। 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश के ही पास रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सबसे कम विभाग रखे हैं। नीतीश के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय और वे सभी विभाग रहेंगे, जो किसी और को आवंटित नहीं किए गए हैं। नीतीश ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से हर कार्यकाल में गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। कानून-व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे संवेदनशील मामलों को वे सीधे तौर पर मॉनीटर करते रहे हैं। अब गृह मंत्रालय मिलने से सम्राट चौधरी बिहार भाजपा में बड़े नेता बनकर उभरे हैं। अब बिहार की कानून व्यवस्था का जिम्मा उनके पास रहेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जेडीयू ने अपने पास रखा है। जेडीयू के विजेन्द्र यादव वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री बने वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है, जिसे सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में से एक माना जाता है। नीतीश ने फिलहाल 26 में से 18 मंत्रियों को विभाग बांटे हैं।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देश के सभी चुनावों में अव्वल और सुर्खियों में रहा। एनडीए को 243 में 202 सीट

की बड़ी जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। जीत के जश्न में डूबे एनडीए कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता का हौसलाअफजायी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से संबोधित करते हुए कहा कि इस जीत ने एक नया 'एमवाई-महिला और यूथ' फॉर्मूला दिया है और जनता ने ''जंगल राज' वालों के सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूले'' को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का विभाजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस 'मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस', यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, इसलिए कांग्रेस के भीतर भी अब एक नया धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है। कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। मुझे आशंका है-हो सकता है, आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस परजीवी है जो साथियों का वोट निगलती। हम बिहार को और देश को विकसित बनाएंगे। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर से जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के कई राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बंगाल में 50 साल से कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आई है। कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनावों में 3 सीटों की संख्या तक भी नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से और हर परंपरा में एनडीए को लोग विश्वास और उम्मीद से देख रहे हैं। महानगरों से गांवों तक, टियर 2-3 शहरों तक, नारी शक्ति से लेकर पहली बार वोट देने वालों तक-सभी ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है और दे रहे हैं। जब रेलवे स्टेशनों पर छठी मईया के गीत गूंजे, तो हर कोई इस पावन पर्व में शामिल हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गले से गमछा हांथो में रखकर खूब लहराया। बता दे कि गमछा बिहार की एक पहचान है और

पीएम मोदी बिहारियों के इमोशन को भांप चुके हैं। सनद् रहे कि पीएम मोदी के भाषण से पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एक जोरदार गीत गया। मनोज तिवारी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर अपने संबोधन में हां हम बिहारी हैं जी, बिहार के आभारी हैं जी गीत गाते हुए गमछा लहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस गमझे का जो सम्मान किया। वह जब मंच पर आएं तो आप सभी इसे लहराइएगा। मनोज तिवारी के साथ मंच पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। वह भी इस गीत के साथ झूमते नजर आए। इस गीत पर दर्शक और भाजपा कार्यकर्ता भी झूमते और नारेबाजी करते दिखे। इस बीच 'मोदी, मोदी', 'भारत माता की जय' के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में उनका स्वागत किया। मंच पर पीएम मोदी ने भी गमछा लहराकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के जनादेश ने 'जंगलराज' के लिए 'नो एंट्री' का बोर्ड लगा दिया है। वही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार की जीत के लिए एक्स पर रिएक्शन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। वही इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी। बिहार की जनता का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों और उनके

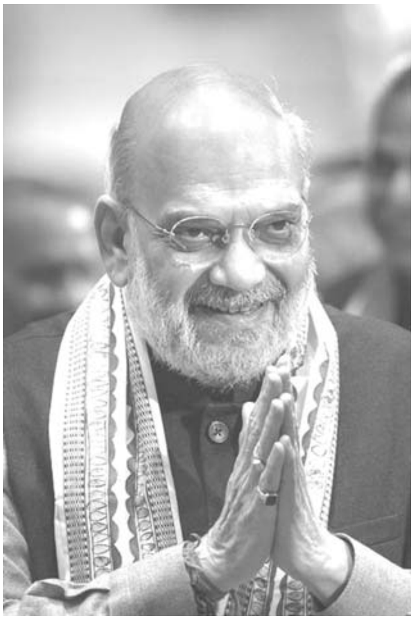

समर्थकों के विरुद्ध मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके विरुद्ध राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर पहुच गई है। उन्होंने कहा कि बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे

देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधनसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की भारी सफलता के लिए मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने इसको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी मार्गदर्शन में बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधनसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की भारी सफलता के लिए मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने इसको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी मार्गदर्शन में बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-राजग गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन। उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और 'डबल इंजन' सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यालय पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत पर जश्न का माहौल है। नेताओं के साथ कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ जीत की दिवाली मना रहे हैं। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर

जश्न मनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर महागठबंधन नेताओं ने खूब बबाल काटा गया। यहां तक की राहुल गांधी ने बिहार के लगभग जिलों में वोटर अधिकार यात्रा तक कर डाली। निर्वाचन आयोग पर कई संगीन आरोप भी लगाये गये। उनकी यात्रा में लोगों की हुजूम भी खूब उमड़ी किन्तु चुनाव परिणाम कुछ और ही निकले। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले राहुल गांधी द्वारा निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' भी बेअसर साबित हुई क्योंकि यह यात्रा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरी वहां भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में बीते 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ थी। यह यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर और कुछ अन्य क्षेत्रों से गुजरी

थी। वही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि निस्संदेह, बिहार चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और निर्वाचन आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी को बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने के संकल्प को दोहराती है। दिगर बात है कि अब राहुल गांधी को लेकर कहा जाने लगा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स हो गया है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर आठ में से एक वोट फर्जी है। राहुल गांधी ने दावा किया था बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया। एक लड़की ने 10 जगह वोटिंग की। फेक फोटो वाले एक लाख 24 हजार 177 मतदाता थे। वोटर लिस्ट में एक महिला ने नौ जगह वोटिंग की। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेन जेड इसे स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि यह आपके भविष्य के बारे में है... मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कर रहा हूं। लेकिन अब बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आये हैं, उससे लग रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स हो गया है। दिलचस्प है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 2 नवंबर को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर भी चर्चा की। उन्होंने यहां एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। बेगूसराय में भाजपा के कुंदन कुमार ने कांग्रेस की अमिता भूषण को 30,632 वोटों से हरा दिया। कुंदन को 1,19,506 वोट मिले जबकि अमिता 88,874 वोट ही हासिल कर सकी। 2020 में भी यह सीट भाजपा के ही पास थी। बेगूसराय विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां 8 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, 3 बार सीपीआई और एक बार निर्दलीय विधायक चुनाव जीत चुके हैं।

बहरहाल, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैरानी जताई है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने परिणामों को आश्चर्यजनक बताया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त

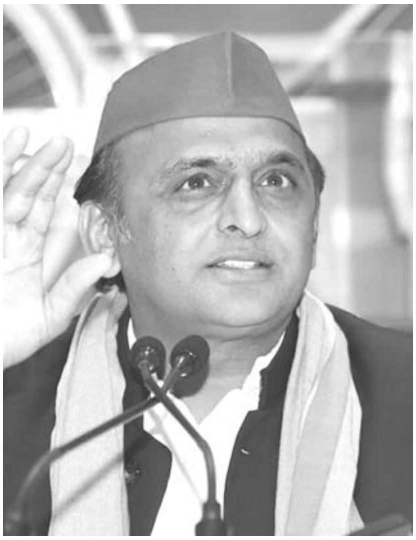

करता हूं जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा। ज्ञात हो कि बिहार में कांग्रेस बड़ी ताकत थी। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर एक बार फिर खड़े होने का संकेत दिया था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उसकी हार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिछले करीब चार दशकों से कांग्रेस की हालत पतली होती चली गई। उसने 1985 में 196 सीटों हासिल की थीं, लेकिन 1990 में घटकर 71 पर आ गई। कांग्रेस ने 1995 और 2000 में क्रमश: 29 और 23 सीटें जीतीं। 2010 में चार सीटों पर सिमट गई, हालांकि महागठबंधन के घटक के तौर पर उसने 2015 में 27 सीटें जीतीं।

बताते चले कि बिहार विधनसभा चुनाव में महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गई। राजद तो 23 फीसदी वोट शेयर प्राप्त कर अपनी साख बचा ली, लेकिन कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। करारी हार के बाद पार्टी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के साथ ही पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने एक खबर का स्क्रिन शॉट शेयर करते हुए कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी-अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए, वे विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर 'वोट चोरी' है। पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एनडीए की सांसद शाम्भवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वे बाहर निकलीं तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी-नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए भेजना जारी रखा। खासतौर पर ये किस्तें वोटिंग के दिनों के आसपास भेजी गईं। मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वे खुद इस 'वोट चोरी' की मिलीभगत में शामिल हैं। अलबत्ता कांग्रेस के सामने पहले से खड़ी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। अब उसे न सिर्फ अपने को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा, बल्कि अगले साल अन्य प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों में

सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल करने तथा अपनी खोई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद करनी होगी। वही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। महागठबंधन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एसआईआर का विरोध करते हुए राज्य में यात्रा निकाली थी। खबरों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव में आज मतगणना का दौर जारी है। बिहार के चुनाव परिणामों के रुझानों ने विपक्षी दलों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव के परिणामों ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है, जहां एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। यादव सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महागठबंधन की हार का जिम्मेदार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भारतीय जनता पार्टी को ठहराया है। उन्होंने विपक्षी खेमे के लिए एक नई रणनीति की भी घोषणा की। अखिलेश ने कहा कि सीसीटीवी की तरह अब पीडीए प्रहरी भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भाजपा छल बताया है। बिडम्बना है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान राजद के चुनावी नतीजों ने किया। वोट प्रतिशत अधिक पाने के बावजूद भी आरजेडी की हार हुई है इसका कारण जीती हुई सीटों की संख्या कम होना है। वह सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी मात्र 25 सीटें ही जीत सकी और तीसरे नंबर पर रही। गौरतलब है कि इस बार बिहार की कुल

243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में ऐतिहासिक 66.91 फीसदी मतदान हुआ। इनमें 6 नवंबर को पहले चरण में कुल 65.08 फीसदी मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 68.76 फीसदी वोटिंग हुई। इस चुनाव में राजद ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस 61, लोजपा रामविलास 29, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत की करें तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट मिले। इसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। बिहार चुनाव में भाजपा को कुल 89 सीटों पर जीत मिली है, जबकि जदयू मात्र 19.25 फीसदी वोट पाकर भी दूसरे स्थान पर रही। भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट मिला है। वोटों की संख्या की बात करें तो राजद को एक करोड़ 15 लाख 46 हजार 55 वोट मिले हैं। वहीं, भाजपा को 20.8 फीसदी यानी एक करोड़ 81 हजार 143 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 8.71 फीसदी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 4.97 फीसदी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) को 2. 84 फीसदी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1.85 फीसदी वोट मिले। जनसुराज पार्टी तो 237 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। बसपा 181 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके खाते में भी मात्र एक ही सीट आई। वो भी उसने मात्र 30 वोटों के अंतर से जीती।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जिस 'तेज' और 'बदलाव' का नारा गूंज रहा था, वह निर्णायक नतीजों के सामने फीका पड़ गया। जहां एनडीए स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से भी काफी नीचे खिसक गए हैं। इस निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं, जिसमें लालू परिवार के भीतर का विवाद और तेज प्रताप यादव के चौंकाने वाले चुनावी हार ने भी अहम भूमिका निभाई है। तेजस्वी यादव का 'तेज' क्यों फीका पड़ा? तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुटाई और '10 लाख नौकरियों' के वादे पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनका यह 'तेज' सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह रही की भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 'जंगलराज' की वापसी का डर दिखाकर वोटरों को एकजुट किया। लालू यादव के जेल में होने और आरजेडी की पुरानी छवि ने कई अति-पिछड़ों और मध्यम वर्ग के वोटरों को एनडीए से जोड़े रखा। इसके साथ ही आरजेडी ने अति-पिछड़ा वर्ग और महादलितों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कोई मजबूत आधार तैयार नहीं किया। वह अब भी मुख्य रूप से एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर अधिक निर्भर रही, जबकि नीतीश कुमार ने ईबीसी और महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखी। वही महागठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस अपने वोट आरजेडी को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हो पाई, जिसने महागठबंधन की जीत की संभावनाओं को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। महागठबंधन के हार का बड़ा कारण महिला फैक्टर को कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं के बीच

अपनी छवि बनाए रखी। शराबबंदी, साइकिल योजना, और पंचायती राज में आरक्षण जैसे कदमों ने महिलाओं के बीच उनके प्रति विश्वास को बरकरार रखा, जिसने एनडीए के पक्ष में निर्णायक रूप से मतदान किया। हैरानी वाली बात तो यह रही कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट पर भी शुरुआती रुझानों में प्रतिद्वंद्वी से पिछड़ने के बाद, कड़े संघर्ष के बाद ही बढ़त बना पाए। उनके अपने राजनीतिक केंद्र में यह संघर्ष पूरे राज्य में उनकी लोकप्रियता पर सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का चुनावी हाल महागठबंधन के लिए एक अलग ही शर्मिंदगी का कारण बना है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गये। शुरुआती रुझानों में, तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर चौथे नंबर पर चल रहे थे, उन्हें अपने पिता की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार और एलजेपी (आर) के उम्मीदवार से भी कम वोट मिले। तेज प्रताप का यह कदम लालू परिवार के भीतर के कलह को सार्वजनिक रूप से दिखाता है। उनका अलग लड़ना और चौथे नंबर पर आना परिवार की एकजुटता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है और आरजेडी के कैडर को भी भ्रमित किया। बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव का 'तेज' फीका पड़ने की मुख्य वजह एनडीए का सफल जातिगत और विकास का संतुलन और महागठबंधन के भीतर कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन व आंतरिक कलह रहा। तेजस्वी की युवा अपील और नौकरी के वादे को जेडीयू के स्थापित सुशासन मॉडल

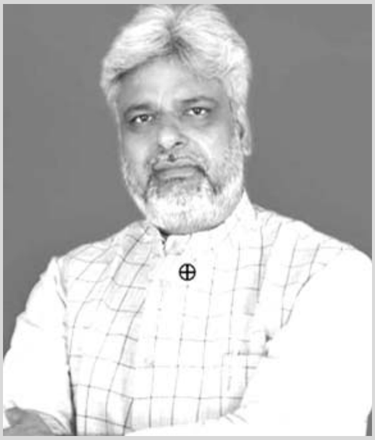

राघोपुर
बिहार विधानसभा का रहा हॉट सीट

एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने परंपरागत सीट राघोपुर से जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार राय को बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि जब तक रूझान आ रहे थे तब तक कभी तेजस्वी आगे होते तो कभी सतीश कुमार राय आगे होते दिखे, आखिर में बाजी तेजस्वी ने मारी और 11 लाख से ज्यादा वोट से जीत गये। उन्होंने 13 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के सतीश कुमार को 102587 वोट हासिल हुए। बता दें कि तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्हें उनके पारिवारिक गढ़ राघोपुर में बीजेपी के सतीश कुमार ने कड़ी टक्कर दी। शाम करीब 4 बजे 20 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी 3,500 से ज्यादा वोटों से आगे थे लेकिन उन्होंने 11 हजार से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। यादव बहुल राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र राजद के प्रथम परिवार का गढ़ रहा है। यहां तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद दो बार (1995 और 2000) जीत चुके हैं। तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने भी यहां पर तीन बार जीत दर्ज की है। वह पहली बार साल 2000 के उपचुनाव में जीतीं और फिर दूसरी बार 2005 के चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की। वही सतीश कुमार भी बिहार की राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते थे। पहले वे जदयू में थे हालांकि बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि 2015 और 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राघोपुर से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यहां से जीतकर उप मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी उनकी उम्मीदें आसमान पर थी लेकिन जिस सतीश कुमार को उन्होंने 2 बार हराया वे ही इस बार राजद के दिग्गज नेता को कड़ी चुनौती दिया।

और बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। तेज प्रताप यादव का अलग लड़ना और चौंकाने वाला प्रदर्शन परिवार की एकजुटता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। दिगर बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार से सियासी विश्लेषकों और चुनावी पूर्वानुमान को भी ध्वस्त कर दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भले ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ खूब आई हो लेकिन चुनाव नतीजे बताते है कि महागठबंधन को बिहार की जनता ने बुरी तरह खारिज कर दिया है। बिहार मे महागठबंधन की रैलियों में आने वाली भीड़ को उसके नेता अपने ही वोट में नहीं बदल पाए। बिहार में महागठबंधन की हार को कारणों का विश्लेषण किया जाए तो एक नहीं कई कारण दिखाई देते है। बिहार में महागठबंधन की हार का बड़ा कारण चुनाव से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद खुलकर सामने आए वह महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। पहले चरण में 122 सीटों पर नामांकन के बाद भी महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाना महागठबंधन की हार का बड़ा कारण सबित हो रहा है। वहीं राहुल और तेजस्वी जो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले एक साथ नजर आ रहे थे वह बाद में एक साथ नहीं दिखाई दिए

जबकि एनडीए नेता पूरे चुनाव में एकजुट नजर आए, वह महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ा। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधन मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे थे तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही चेहरे थे, ऐसे में चुनाव दो चेहरों के बीच था और अब चुनाव नतीजे बताते है कि तेजस्वी यादव पर नीतीश का चेहरा भारी पड़ गया। एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से पूरे चुनाव में नीतीश के चेहरे को आगे रखा, वह कारगर होता हुआ दिखाई दिया। एनडीए नेताओं ने जिस तरह से चुनाव में तेजस्वी के चेहरे को लालू यादव से जोड़ा वह चुनावी दांव चल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के लगातार भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी होने का मुद्दा उठाया उसने युवाओं में तेजस्वी के क्रेज को फीका करने में अहम फैक्टर साबित हुआ। और तो और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे है कि तेजस्वी यादव को एक बार राहुल गांधी से दोस्ती यानि कांग्रेस से गठबंधन भारी पड़ गया। बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और वह 6 सीट ही जीत पायी, जो महागठबंधन की हार का बड़ा कारण साबित हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते है कि चुनाव में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रो इनकंबेंसी थी। नीतीश के सुशासन राज पर बिहार की जनता ने

अपना विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से समाज के हर वर्ग को साधने का दांव चला और भाजपा ने जिस तरह से गठबंधन में नीतीश के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा, उससे यह साफ है कि चुनाव में नीतीश सरकार के प्रति एक प्रो इनकबेंसी बनाने का काम किया। इसके अलावा मुख्य कारण जो बताये जा रहे हैं वह है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा और जेडीयू नेताओं ने लालूराज और जंगलराज को मुद्दा बनाकर अक्रामक चुनावी कैंपेन किया गया, वह महागठबंधन की हार का बड़ा कारण बना। लालूराज में जिस तरह से बिहार में अपराध का बोलबाला रहा है, उसको चुनाव में एनडीए ने खूब उछाला। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने चुनावी रैलियों में कहा कि अगर भैया की सरकार आई तो कट्टा और फिरौती का दौर फिर से लौट आएगा। चुनाव नतीजे बताते है कि यह मुद्दा खुब चला और वोटर्स ने एनडीए के पक्ष में खूब मतदान किया।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सीटे पिछले चुनाव के मुकाबले आधे से भी कम रहे। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ा दल बना था। हालांकि तेजस्वी को इस बात का संतोष हो सकता है कि कम सीटों के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस चुनाव में एक बात स्पष्ट तौर पर निकलकर आएगी है कि 'कमजोर' कांग्रेस का साथ तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया। क्योंकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत तुलनात्मक रूप से काफी कम रहा। न तो राहुल गांधी की पदयात्रा काम आई और उनका हाइड्रोजन बम भी 'फुस्स' हो गया। महागठबंधन की ओर से पूरे समय तेजस्वी यादव ही एकमात्र ऐसे नेता रहे, जो चुनाव प्रचार में जुटे रहे। परिवार की कलह का भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन में आखिरी समय तक सीटों के बंटवारे को लेकर मारामारी रही, इसके कारण मतदाता के मन में 'कनफ्यूजन' पैदा हुआ और परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस ने कभी भी खुले मन से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया। ऐन मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। मीडिया के पूछने के बाद राहुल ने गोलमोल जवाब दिया। चुनाव के दौरान राहुल गांधी लगभग पूरे समय गायब रहे, इसका भी नकारात्मक असर हुआ। वही दूसरी ओर डिप्टी सीएम का सपना लेकर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का बुरा हाल हुआ। एनडीए गठबंधन सरकार में मुकेश सहनी को मछलीपालन मंत्री का पद मिला था लेकिन 2022 में सरकार गिर गई और उनका मंत्री पद भी चला गया। महागठबंधन में आने के बाद वे तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताने लगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने पर मुकेश सहनी को सरकार में डिप्टी सीएम पद देने का ऐलान किया था। नीतीश ने सहनी पर बहुत भरोसा किया था। महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी फिसड्डी प्लेयर साबित हुए जिस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया था। 'सन ऑफ मल्लाह' की नाव इस चुनाव में पार नहीं हो सकी। इस हार के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। माताओं-बहनों का वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे कि विफल होने का क्या कारण है। बता दें कि परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे। खुद तेजप्रताप की महुआ में हालत खराब रही। महागठबंधन की हार पर तेजप्रताप ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद को जगह नहीं है। 5 अगस्त को बिहार की 5 छोटी पार्टियों वंचित विकास इंसान पार्टी, भोजपुरीया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी के साथ गठबंधन का एलान किया। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन और संजय सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। महुआ सीट पर 14वें राउंड की काउंटिंग के बाद तेज प्रताप यादव काफी पीछे चले गये। बता दें कि पारिवारिक कलह के कारण यह सीट और भी महत्वपूर्ण रहा।

बताते चले कि इस चुनाव में महागठबंधन के कई दिग्गजों को हार का सामना

सौ साल पुरानी भाकपा का विधानसभा चुनाव में नहीं खुला खाता

विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल भाकपा ने नौ सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें चार ऐसी सीटें थीं जहां कांग्रेस के साथ ही संघर्ष था। इसके बाद सभी सीटों पर भाकपा को हार मिली। जानकारी के मुताबिक 1951 से अब तक हुए चुनाव में यह दूसरा मौका है जब भाकपा को एक भी सीट नहीं मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में एक, 1957 में सात, 1962 में 12, 1967 में 25, 1969 में 25, 1972 में 35, 1977 में 21, 1980 में 22, 1985 में 12, 1990 में 24, 1995 में 26 , 2000 में 5, 2005 में 3, 2005 में 3, 2010 में 1, 2015 में 00, 2020 में 2 और 2025 में शून्य पर आउट हो गयी।

करना पड़ा। जिनमें 5 सीटें ऐसी रही जहां पर जीत का आंकड़ा सबसे कम रहा। बिहार चुनाव में सबसे छोटी जीत जदयू नेता रामचरण साहू की है। उन्होंने संदेश सीट पर राजद के दीपू सिंह को मात्र 27 वोटों से मात दी। रामचरण को 80,598 मिले तो दीपू सिंह के पक्ष में 80571 वोट गिरे। जनसुराज के राजीव रंजन राज 6000 से ज्यादा वोट प्राप्त कर तीसरे नंबर पर थे। रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा के सतीश कुमार यादव मात्र 30 वोटों से जीत दर्ज करने में सफल रहे। उन्हें 72,689 वोट मिले तो भाजपा के अशोक कुमार सिंह 75,659 वोट ही हासिल कर सके। त्रीकोणिय मुकाबले वाली इस सीट पर राजद के अजीत कुमार 41 हजार से ज्यादा वोट ले गए। भाजपा नेता महेश पासवान ने अगिआंव सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) के प्रत्याशी शिव प्रकाश रंजन को मात्र 95 वोट से हराया। पासवान को 69412 वोट मिले जबकि शिवप्रकाश को 69317 ही हासिल हुए। यहां जनसुराज के रमेश कुमार 3882 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। जदयू नेता चेतन आनंद ने राज्य की नबीनगर विधानसभा सीट पर मात्र 112 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। चेतन आनंद को 80,380 वोट मिले जबकि राजद के अमोद कुमार सिंह 80,268 वोट हासिल कर जीत से कुछ ही कदम दूर रह गए। निर्दलीय प्रत्याशी लव कुमार 7000 से ज्यादा वोट लेकर नंबर 3 पर रहे। बिहार की ढाका सीट पर राजद के फैसल रहमान ने भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को मात्र 178 वोटों से हराया। यहां जनसुराज पार्टी के डॉक्टर एलबी प्रसाद ने 8347 वोट प्राप्त किए। बिडम्बना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की भूमिका पर अब गहन चर्चा शुरू हो गई है। आधिकारिक परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम चार विधानसभा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने इतने वोट काटे कि जीत-हार का पूरा गणित बदल गया। इनमें सबसे चर्चित नाम परिहार की रितु जायसवाल हैं, जिन्होंने 31.53 प्रतिशत वोट हासिल कर महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार को हरवा दिया। सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट पर बीजेपी की रितु जायसवाल ने बतौर निर्दलीय 65,455 वोट (31.53%) हासिल किए। विजेता बीजेपी के ही गायत्री देवी को 68,000 से कुछ अधिक वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार सीमा गुप्ता को करीब 50 हजार वोट मिले। मतलब साफ है, रितु जायसवाल के वोट यदि महागठबंधन को जाते तो परिहार की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती। बीजेपी ने रितु को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने बागी तेवर अपनाए और पार्टी के लिए ही सबसे बड़ा झटका दे दिया। वही पूर्णिया के कुशेश्वर स्थान (एससी) सीट पर निर्दलीय गणेश भारती ने 49,244 वोट (31.26%) लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। विजेता जेडीयू उम्मीदवार को 52 हजार के करीब वोट मिले। तीसरे नंबर पर जनसुराज के उम्मीदवार रहे। गणेश भारती पूर्व में जेडीयू से जुड़े रहे थे और टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरे। उन्हें महागठबंधन का समर्थन मिला था। कैमूर जिले की मोहनिया (एससी) सीट पर निर्दलीय रविशंकर पासवान ने 57,538 वोट (30.63%) हासिल किए। विजेता बीजेपी उम्मीदवार को लगभग 62 हजार वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर बीएसपी उम्मीदवार रहे। रविशंकर पासवान को महागठबंधन का

एक भी निर्दलीय उम्मीदवार सदन तक नहीं पहुंच सका

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात सबसे दिलचस्प रही। इस बार इस बार एक भी निर्दलीय उम्मीदवार सदन तक नहीं पहुंच सके। ज्ञात हो कि बिहार-झारखंड अलग होने के बाद यानी पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। जो उम्मीदवार कभी बिना पार्टी के सहारे जनता के भरोसे जीतकर आते थे, वे अब पूरी तरह हाशिए पर पहुंच गए हैं। 2005 में जहां 17 निर्दलीय जीते थे, वहीं 2010 में 6, 2015 में 4, 2020 में सिर्फ 1 और 2025 में यह संख्या शून्य हो गई। इनके कई कारण बताये जा रहे हैं। बता दें कि इस बार जदयू, राजद, लोजपा, हम, लोजपा जैसे दलों ने हर गांव, हर पंचायत और हर बूथ तक अपनी पकड़ बनाई है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए वोटरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जनता स्पष्ट विकल्प चाहते थें और दलों की मौजूदगी में निर्दलीयों की जमीन सिकुड़ गई। इसके साथ ही एक कारण बड़े पैसों का खेल। चुनाव लड़ना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। बड़े दल करोड़ों रुपये के संसाधन लगाते हैं-टीमें, गाड़ियां, सोशल मीडिया प्रचार, बूथ प्रबंधन, सबकुछ बेहद संगठित तरीके से होता है। निर्दलीयों के पास न तो इतना पैसा होता है और न ही इतना बड़ा नेटवर्क। परिणाम यह कि उन्हें प्रचार के दौरान वह दृश्यता ही नहीं मिल पाती, जो जीत के लिए जरूरी होती है। हालांकि स्वतंत्र नेता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा खुलकर आवाज उठाते हैं यह भी सच है। कई चुनावों में यही वजह रही कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने जनता का भरोसा जीता। लेकिन अब जनता चाहती है कि उनकी बात बड़े मंच पर सुनी जाए। स्वतंत्र नेता चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन बिना पार्टी का सहारा उनकी आवाज विधानसभा में कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि लोग अच्छे उम्मीदवार का समर्थन करते हुए भी उन्हें वोट नहीं दे पा रहे। नतीजा साफ है-बिहार में निर्दलीयों का दौर लगभग खत्म हो चुका है।

समर्थन हासिल था। अगर इनमे वोट बीएसपी को जाते तो वह चुनाव जीत सकते थे। वही जमुई की चकाई सीट पर दो निर्दलीयों संजय प्रसाद (48,065 वोट, 21.05%) और चंदन कुमार सिंह (12,502 वोट) ने कुल मिलाकर 26% से अधिक वोट काट लिए, जिससे आरजेडी की सावित्री देवी विजयी रहीं। इन्होंने जेडीयू के मंत्री सुमीत सिंह को मात दी। यहां निर्दलीय उम्मीदवार संजय प्रसाद को 48065 वोट मिले, जिसने सीट का रुख तय किया। इन चार सीटों को छोड़कर बाकी निर्दलीयों का असर सिर्फ वोट प्रतिशत तक सीमित रहा। सिकटा में खुरशीद फिरोज अहमद (24.26%), रुपौली में शंकर सिंह (13. 68%), गोबिंदपुर में मोहम्मद कामरान (22. 56%), बरबीघा में सुदर्शन कुमार (20.56%) जैसे कई निर्दलीयों ने 20% से ऊपर वोट लिए, लेकिन विजेता और उपविजेता के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि वोट एकतरफा होने पर भी नतीजा नहीं बदलता। बता दें कि इस बार बिहार में बागियों और निर्दलीयों की संख्या पिछले चुनावों से काफी अधिक रही। बीजेपी, जेडीयू, राजद और कांग्रेस सभी दलों के असंतुष्ट नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। परिणामस्वरूप करीब 35-40 सीटों पर 10% से अधिक वोट निर्दलीयों को मिले। हालांकि सिर्फ चार सीटों पर ये निर्णायक साबित हुए।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी राजनीतिक पहल जन सुराज के लिए एक बड़ी निराशा लेकर आए हैं। व्यापक प्रचार और जमीन पर लंबे समय तक काम करने के बावजूद, जन सुराज के उम्मीदवारों ने कहीं भी निर्णायक बढ़त नहीं बनाई और शुरुआती रुझानों में भी उनका खाता नहीं खुला। इस प्रदर्शन ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के उस बड़े दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। बता दें कि जन सुराज ने बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल पेश करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी अखाड़े में वह बुरी तरह विफल रहा। शुरुआत से लेकर अंतिम रुझानों तक, जन सुराज के किसी भी उम्मीदवार ने राज्य की 243 सीटों में से किसी भी सीट पर बड़ी बढ़त हासिल नहीं की। अधिकांश उम्मीदवारों की स्थिति इतनी कमजोर रही कि उनकी जमानत तक जब्त होने की आशंका है। जन सुराज की रणनीति पदयात्रा, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें और स्थानीय समस्याओं पर फोकस करने की थी। ऐसा लगता है कि यह रणनीति सीधे मतदाताओं को खींचने में विफल रही, जो अभी भी जातिगत समीकरणों, बड़े दलों के गठबंधनों और स्थापित चेहरों पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर एक मजबूत चेहरा हैं, लेकिन उनकी पहल किसी स्थापित कैडर या संगठनात्मक ढांचे पर आधारित नहीं थी। चुनाव में जीत के लिए जो मजबूत बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता नेटवर्क चाहिए, जन सुराज वह प्रदान नहीं कर पाया। जन सुराज ने उन सीटों पर भी कुछ हद तक वोट बटोरे जहां मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच था। हालाँकि, ये वोट इतने कम थे कि वे केवल वोट काटने वाले की भूमिका में ही सिमट कर रह गए। प्रशांत किशोर ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि अगर वह बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव

बिहार के मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम पर जता रहे भरोसा

असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीट पर जीत दर्ज की। 2020 के चुनाव में भी एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीती थी, हालांकि बाद में उनके एक विधायक को छोड़कर सभी ने राजद का दामन थाम लिया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का माय समीकरण पर एआईएमआईएम ने सेंध लगायी है। कल तक मुसलमानों के लिए बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे किन्तु अब के हालात बयां करते हैं कि एआईएमआईएम उनका विकल्प बनता जा रहा है, खासकर सीमांचल के मुसलमान राजद को छोड़कर एआईएमआईएम पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और इसका प्रमाण है एआईएमआईएम की जीती पांच सीटें। महागठबंधन के बड़े और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की 6 सीटों के सामने एआईएमआईएम की 5 सीटें कितने मायने रखते हैं। बता दें कि एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाली इस पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों में से 29 पर चुनाव लड़ा। जिन सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, उनमें से 24 सीट सीमांचल क्षेत्र की हैं। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने अमौर सीट पर 38,928 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 1,00,836 वोट मिले। मोहम्मद सरवर आलम ने कोचाधामन में 23,021 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें कुल 81,860 वोट मिले। गुलाम सरवर ने बैसी सीट पर 27,251 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 92,766 वोट मिले। मोहम्मद मुर्शीद आलम ने जोकीहाट सीट पर 28,803 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 83,737 वोट मिले। बहादुरगंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें 87,315 वोट मिले।

नहीं ला पाते हैं या उनके प्रयासों को जनता का समर्थन नहीं मिलता है, तो वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने विभिन्न मीडिया चैनलों पर कहा था 'मेरा यह प्रयास अगर विफल हुआ और जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा'। अब सवाल है कि क्या शून्य सीटों और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर अपना यह वादा निभाएंगे? चुनावी परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जन सुराज को जनता का वह व्यापक समर्थन नहीं मिला जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अपने इस निराशाजनक प्रदर्शन को कैसे व्याख्यायित करते हैं। क्या वह इसे 'विफलता' मानकर पीछे हटते हैं या अपनी पदयात्रा को अगले चरण के लिए एक आधार मानते हुए अपनी प्रतिज्ञा से मुकर जाते हैं। बिहार की राजनीति अब भी जाति आधारित सामाजिक गठबंधनों और बड़े दलों के बीच ध्रुवीकरण से चलती है। 'वैकल्पिक' या 'विचारधारा-आधारित' राजनीति के लिए यहां तत्काल कोई जगह नहीं है। वही नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे स्थापित नेताओं की पकड़ अब भी बिहार के मतदाता पर बरकरार है, जिसे एक नए चेहरे या पहल से तुरंत चुनौती नहीं दी जा सकती। जन सुराज का यह प्रदर्शन प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और स्पष्ट कर दिया कि वे बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब सलाह नहीं संघर्ष करने के समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने अपनी बात ठीक ढंग से जनता को नहीं बताई। उस कारण शायद जनता ने वोट नहीं दिया। खुद पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि वे जिस विश्वास की उम्मीद कर रहे थे, वह विश्वास नहीं जीत पाए। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 से अधिक लाभार्थियों को 10,000 रुपये नहीं दिए होते तो जेडीयू 25 सीट भी नहीं जीत पाती। इससे जेडीयू के सीटों की संख्या बढ़ी। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए सरकार ने जनता के पैसों से 40,000 करोड़ रुपये की घोषणाएं कीं और चुनाव से ठीक पहले बहुत पैसे बांटे। उन्होंने कहा कि 'मैं बिहार को समझने में नाकाम रहा। हमने लोगों को मुद्दे समझाने की ईमानदार कोशिश की लेकिन चुनाव नतीजे बेहतर नहीं आए। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी पार्टी से कोई विधायक नहीं बना लेकिन अब जनता के बीच जाकर संघर्ष करेंगे। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, आप तब तक नहीं हारते, जब तक आप खेल छोड़ नहीं देते। मेरी पार्टी ने न तो समाज को बांटा और न ही लोगों के वोट खरीदे हैं।'

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके

हैं। दूसरी ओर, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने विधायक दल की बैठक में तेजस्वी को भविष्य का नेता बताया और कहा कि वह आगे भी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि विधायक चाहें तो मैं नेतृत्व छोड़ने को तैयार हूं। वे किसी और को भी अपना नेता चुन सकते हैं। तेजस्वी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि विधायकों को लगता है कि उनके स्थान पर किसी और के आने से संगठन मजबूत हो सकता है तो वे ऐसा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी पार्टी की हार को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर काफी आहत हैं। टिकट वितरण के मामले में भी उन पर आरोप लगे हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने उनके करीबी संजय यादव एवं रमीज नेमत खान पर भी आरोप लगाए हैं। हालांकि बैठक में विधायकों ने कहा कि आप ही हमारे नेता रहेंगे। इसके बाद विधायकों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी को अपना नेता चुन लिया। हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ही विधायक दल के नेता होंगे। बैठक के दौरान लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने बैठक में कहा कि इस तरह के परिणाम की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में हमने एक-एक सीट का फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से यह जांचने के लिए कहा कि क्या ईवीएम के वोट और उनके आकलन में अंतर है? इस मामले में यदि कोई सबूत सामने आता है तो हम कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की बुरी हार हुई है। उसे सिर्फ 25 सीटें ही प्राप्त हुई हैं, जो कि 2020 के मुकाबले 50 कम हैं। यदि राजद को 2 सीटें और कम मिलतीं तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी उससे छिन जाता।

विदित हो कि बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। ऐसे में हर वर्ग के मतदाता या वोटर्स यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके जाति के कितने एमएएलए जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं? बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट आने के बाद कई जातियों की सीटों के समीकरण में काफी उतार-चढ़ाव आया है। साल 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार कितने भूमिहार, राजपूत, कोइरी यानी कुशवाहा, कुर्मी, यादव और ब्राह्मण जातियों के कैंडिडेट जीतकर विधानसबा पहुंचे हैं? लेकिन एक जाति ने इस बार के चुनाव परिणाम में सबको चौंका दिया है। इस जाति का लंबे समय के बाद बिहार में अगले पांच साल तक दबदबा रह सकता है? राजनीतिक पंडितों के लिए यह विश्लेषण जरूरी है कि इस जीत के बाद अगले 5 साल तक बिहार विधानसभा में किस जाति के विधायकों का नीति-निर्धारण में वर्चस्व रहेगा? बिहार की राजनीति में जातीय पहचान सबसे मजबूत आधार मानी जाती है और मंत्रिमंडल गठन के साथ-साथ अगले विधानसभा तक इसी जातीय समीकरण का असर दिखेगा। बता दें कि इस बार अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के 65-75 एमएलए जीतकर आए हैं। कुशवाहा यानी कोइरी, तेली, मल्लाह, नाई, नुनिया जाति के विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। अगर बात पिछड़ा वर्ग की करें तो इस वर्ग से 55-65 विधायक चुनकर आए हैं। इसमें यादव, कुर्मी, वैश्यों की उपस्थिति मजबूत है। 2020 में विधानसभा में यादवों की संख्या 55 थी तो 2025 में उनकी संख्या घटकर सिर्फ 28 रह गई। 2015 में यादव 61 सीटों पर चुनाव जीते थे। ज्यादातर आरजेडी के थे। लेकिन इस बार इनकी संख्या काफी कम हो गई है। बिहार चुनाव कुशवाहा और कुर्मी जाति के लिए यादगार रहा। 2020 में 10 कुर्मी विधायक थे, जो इस बार बढ़कर 25 हो गई है। वहीं, कुशवाहा 16 से बढ़कर इस बार 26 पहुंच गई है। वैश्य 22 से बढ़कर 26 तक पहुंच गए हैं। वही इस बार अपर कास्ट यानी सामान्य वर्ग में सबसे मजबूत प्रदर्शन राजपूतों ने किया है। राजनीतिक दलों ने खासकर एनडीए ने सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया था। 2020 चुनाव में राजपूत एमएलए की संख्या 18 थी, जो इस बार बढ़कर 32 सीटों तक पहुंच गई है। इस बार भूमिहार जाति के कैंडिडेट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2020 में जहां इस जाति के 17 विधायक थे, वहीं 2025 में भूमिहार जाति के 23 विधायक हो गए हैं। दोनों ही जातियों की सीटों में बढ़ोतरी से यह साफ है कि इस बार अपर कास्ट के वोटर्स ने एकजुट होकर वोट किया है। वही बिहार चुनाव 2025 में ब्राह्मणों की संख्या में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। 2020 में 12 ब्राह्मण जीते थे तो इस बार 14 विधायक जीतकर आए हैं। कायस्थ जाति का हाल भी 2020 जैसा ही हुआ है। जहां 2020 में कायस्थ विधायक 3 थे तो वहीं 2025 में 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। कुल मिलाकर अगर ओवर ऑल जातियों की बात करें तो राजपूतों का बिहार विधानसभा में दबदबा रहेगा। क्योंकि इस बार राजपूत विधायक 32, यादव विधायक 28 जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बाद 26 वैश्य, 23 भूमिहार, इसके बाद 26 कुशवाहा, 25 कुर्मी, 14 ब्राह्मण और 2 कायस्थ विधायकों का नंबर आता है। इसके साथ ही ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के 13, दलितों के अलग-अलग जातियों से 36 और 11 मुस्लिम विधायक सदन पहुंचे हैं। वही दूसरी तरफ अगले 5 वर्षों तक संख्यात्मक रूप से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का दबदबा बना

ना विधायक ना एमएलसी, फिर भी मंत्री बनाये गये दीपक प्रकाश

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को भी शपथ दिलाई गई है जो इस बार चुनाव नहीं लड़े थे। इनका नाम है दीपक प्रकाश। अभी ना ही वह विधायक हैं और ना ही एमएलसी। अब उन्हें सरकार में बने रहने के लिए छः महीने के भीतर बिहार विधान परिषद् का सदस्य बनाया जायेगा। दीपक प्रकाश बिहार के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक प्रकाश कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। अब वह एमएनसी की नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। 2024 में पावर स्टार पवन सिंह की चुनावी आंधी में काराकाट से उपेन्द्र कुशवाहा हार गये थे, बाद में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट से उनकी पत्नी स्नेहलता जीत कर सदन पहुंची है और बेटा दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज के मंत्री बनाये गये हैं। इसके बाद से विपक्ष खुले तौरपर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है।

रहेगा, जो नीतीश कुमार के राजनीतिक आधार का मुख्य स्तंभ है। ईबीसी और दलित वर्ग के विजेताओं की कुल संख्या 120 से अधिक होने का अनुमान है, जो विधानसभा में निर्णायक भूमिका में होंगे।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार कैबीनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलाकर कुल 27 मंत्री को शामिल किया गया है, जिसमें कई चेहरे नये हैं जो सरकार के विभाग संभालेंगे। इनमें पहला नाम दीपक प्रकाश का आता है। दीपक प्रकाश आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वे बिहार में चुनाव लड़े बिना ही नीतीश मंत्रिमंडल का चेहरा बन गए। पहले कहा जा रहा था कि उपेंद्र की पत्नी स्नेहलता मंत्री बनेगी लेकिन ऐन वक्त पर दीपक को मंत्री मंडल में जगह मिल गई। बहरहाल दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से चुन

कर आईं रमा निषाद को भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया है। मुजफ्फपुर के पूर्व सांसद अजय

निषाद की पत्नी और कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू रमा को बिहार में भाजपा का नया चेहरा बताया जा रहा है। वही शूटिंग में भारत को कई अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाने वाली 34 वर्षीय श्रेयसी सिंह को भी भाजपा के कोटे से मंत्री बनाया गया है। वे राज्य की सबसे युवा मंत्री है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी लगातार दूसरी बार जमुई से विधानसभा चुनाव जीती हैं। मंत्रियों की लिस्ट में एक बड़ा नाम पर नीतीश कैबीनेट में नया चेहरा अनुभवी नेता हैं रामकृपाल यादव को बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी भाजपा के कोटे से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नीतीश कुमार की सरकार में पहली बार उन्हें राज्य में मंत्री बनने का मौका मिला है। वे पाटलीपुत्रा लोकसभा सीट से दो बार सांसद और केन्द्र में मंत्री तक रह चुके हैं। वही भोजपुर की

कभी लालू के थे खास, अब नीतीश सरकार में संभालेंगे कृषि विभाग

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा कोटे से रामकृपाल यादव को भी मंत्री का शपथ दिलाया, उन्हें बिहार कैबिनेट में कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। यह विभाग महत्वपूर्ण माना जाता है। मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्तित्व की छवी रखने वाले रामकृपाल यादव ने दानापुर विधानसभा सीट से राजद के रीतलाल यादव को हराकर विधायक बने हैं। बता दें कि पटना में रेलवे जंक्शन से सटे गोरिया टोली के रहने वाले और 12 अक्टूबर 1951 को जन्मे रामकृपाल यादव ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी पटना के स्थानीय निकायों से ही की थी। वह पटना के मेयर बने फिर धीरे-धीरे जमीनी नेता बन गए और लालू की टीम का हिस्सा हो गए। राजद के टिकट पर वह तीन बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2014 में जब उन्होंने राजद से नाता तोड़कर मीसा भारती के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया। इस पर रहते हुए उन्होंने 2014 से 2019 तक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, आवास और मनरेगा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर कई काम किए। 1990 और 2000 के दशक में वह लालू के हनुमान कहे जाते रहे हैं। वह लालू के सबसे करीबी लोगों में थे, जो साए की तरह हमेशा उनके साथ रहा करते थे। लालू-राबड़ी कार्यकाल में और बाद तक राम और श्याम (रामकृपाल यादव और श्याम रजक) की जोड़ी बिहार में चर्चा रहती थी। रामकृपाल करीब तीन दशकों तक लालू के सबसे भरोसेमंद सिपाही बने रहे लेकिन 2014 में दोनों की राहें जुदा हो गईं। दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनावों में जब लालू यादव ने पाटलीपुत्र संसदीय क्षेत्र से अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को राजद का उम्मीदवार बनाया तो लालू के हनुमान और समाजवादी चेहरा रामकृपाल भाजपा के पाले में चले गए। उनके इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी क्योंकि अब तक वह न सिर्फ लालू के भरोसेमंद सिपाही थे बल्कि उससे भी ज्यादा रणनीतिकार थे जो पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक लालू का संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे। 2019 में वह फिर सांसद चुने गए लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में मीसा भारती के हाथों उनकी हार हुई। ऐसे में पार्टी ने उन्हें पटना से सटे दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वे जीतकर नई सरकार में कृषि मंत्री बने। बड़ी बात यह भी कि इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने खुद लालू यादव दानापुर गए थे, लेकिन जीत रामकृपाल की हुई।

आरा सीट से विधायक चुने गए संजय सिंह टाइगर भी भाजपा के कोटे से मंत्री बने हैं। 2010 में वे भोजपुर के संदेश विधनसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद और लखेंद्र कुमार रोशन भी नीतीश सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने शपथ लेने के साथ ही यह साफ कर दिया है कि इस बार मंत्रिमंडल में जातीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है। सत्ता समीकरण को मजबूत करने और सभी सामाजिक वर्गों को साथ लाने के लिए एनडीए ने लगभग हर प्रमुख जाति और समुदाय को मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश की है। बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नई टीम में सवर्ण, ओबीसी, दलित, महादलित, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, यादव, महिलाएं और मुसलमान सभी वर्गों को मौका दिया गया है। इस बार कैबिनेट में कुल 8 सवर्ण, 8 ओबीसी, 5 दलित-महादलित, 6 कुर्मी-कुशवाहा, 2 यादव, 2 निषाद, 4 वैश्य और साथ ही मुसलमान व महिलाओं को भी शामिल किया गया है। नीतीश सरकार ने जातीय बैलेंसिंग को केंद्र में रखकर अपनी नई टीम तैयार की है। बता दें कि राजपूत समुदाय से 4 मंत्रियों में श्रेयसी सिंह (जमुई), संजय कुमार सिंह

(महुआ), संजय सिंह टाइगर (आरा), लेसी सिंह (धमदाहा) हैं। वही इस चुनाव में 32 राजपूत विधायक जीतकर आए, जिनमें से अधिकतर एनडीए से हैं। वही दलित समुदाय से 4 मंत्रियों में सुनील कुमार (भोरे), अशोक चौधरी (एमएलसी), लखेंद्र रौशन (पातेपुर) और संजय पासवान (बखरी) हैं। एक मंत्री महादलित को बनाया गया है, जो हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन (मुसहर समुदाय) हैं। बात कुर्मी-कुशवाहा समुदाय के मंत्रियों करें तो इनमें 5 मंत्री नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री, कुर्मी), सम्राट चौधरी, सुरेंद्र मेहता, दीपक प्रकाश, श्रवण कुमार शामिल हैं। बिहार सरकार के नये कैबिनेट में वैश्य समुदाय से 4 मंत्री बनाये गये हैं, जिनमें दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार और अरुण शंकर प्रसाद (सूड़ी समाज) हैं। वही भूमिहार-ब्राह्मण समुदाय से 3 मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी (भूमिहार), मंगल पांडे (ब्राह्मण), विजय कुमार सिन्हा (भूमिहार) को बनाया गया है। कायस्थ समुदाय से एक मात्र नितिन नवीन को फिर से मंत्री बनाया गया है। निषाद/मल्लाह समुदाय से 2 मंत्री मदन सहनी और रमा निषाद हैं तथा यादव समुदाय से 2 मंत्री रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव हैं। बता दें कि नीतीश कैबीनेट में पुनः एक मुसलमान समुदाय के मंत्री जमा खान (चैनपुर, जदयू) को बनाया गया है।

विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव

2025 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठला दिया है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ 202 सीटें जीतकर बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। वहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटकर बुरी तरह से धराशायी हो गया। लेकिन, सबसे बड़ी और करारी और चौंकाने वाली हार उस नाम की हुई, जिसने नई राजनीति का दावा किया था यानी प्रशांत किशोर। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद 202 का आंकड़ा छूना वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो वह है तीन किश्तों में 1.21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालना। इस तरह महिलाओं के खाते में कुल 12000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना ने चुनाव का पासा ही पलटकर रख दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि 2020 में 43 सीटें जीतने वाले नीतीश की सीटों की संख्या बढ़कर इस बार 85 हो गई। यानी दोगुनी। भाजपा भी 74 से बढ़कर 89 पर पहुंच गई। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि इस बार बिहार में एनडीए की सुनामी आ गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला केंद्रित अन्य योजनाएं, जैसे 'लखपति दीदी' और 'जीविका दीदी' ने महिलाओं को रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने एनडीए पर अटूट भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और 'मोदी की गारंटी' का फायदा भी एनडीए को मिला। इस चुनाव में 71.6 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों (62.8%) से लगभग 9 फीसदी अधिक था। महिलाओं की इस रिकॉर्ड भागीदारी को एनडीए की प्रचंड जीत का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की नकद राशि का सीधा हस्तांतरण बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हुआ। यह एक ऐसा लाभ था जो महिलाओं को 'वादे' के रूप में नहीं, बल्कि 'डिलीवरी' के रूप में मिला, जिसने उनके मतदान व्यवहार को सीधे प्रभावित किया। महिलाएं बिहार में 'गेमचेंजर' रहीं। उधर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल महज 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिलीं। महागठबंधन की हार के पीछे कई कारण रहे। पहला, स्थानीय नेतृत्व की कमी और कमजोर चुनावी संगठन। विपक्ष की ओर से पूरे चुनाव में एकमात्र नेता तेजस्वी यादव ही नजर आए। दूसरा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर तेजस्वी का पूरा प्रचार महिलाओं के कल्याणकारी वोट बैंक को भेदने में नाकाम रहा। तेजस्वी का महिलाओं को 30 हजार रुपए देने का 'वादा' भी काम नहीं आया। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वाम

दलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को बिहार में महागठबंधन की कमजोर स्थिति का अंदेशा था। हार की स्थिति में, ठीकरा उन पर न फूटे, इसलिए जानबूझकर दूरी बनाई गई। शुरूआती दौर में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर लंबे समय तक खींचतान चली। राहुल गांधी ने चुनाव के शुरुआती दौर में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली और 'वोट चोरी' के आरोपों पर अपना पूरा अभियान केंद्रित किया। हालांकि, चुनावी परिणामों से पता चलता है कि मतदाताओं ने इन आरोपों को महत्व नहीं दिया। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम पूरी तरह 'फुस्स' हो गया। बताते चले कि राहुल गांधी की बिहार चुनाव प्रचार से दूरी एक रणनीतिक जोखिम था, जिसे कांग्रेस ने अंतत: खराब चुनावी प्रदर्शन के रूप में भुगता। विपक्ष की ओर से सिर्फ तेजस्वी यादव ही किला लड़ाते नजर आए। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने युवा बनाम अनुभवी के दांव में सुशासन, अनुभव और स्थिरता को चुना। लेकिन इस पूरे चुनाव का सबसे बड़े 'लूजर' प्रशांत किशोर रहे। एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर कई राज्यों में जीत दिलाने का दम भरने वाले प्रशांत की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उनके 98 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। प्रशांत किशोर ने खुद कम से कम 10 से 150 सीटें जीतने का दावा किया था। उनकी यह बुरी हार यह साबित करती है कि एक सफल रणनीतिकार होना और एक सफल राजनेता बनना दो अलग बातें हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत, जिसका श्रेय महिला शक्ति के साथ ही मोदी-नीतीश के कल्याणकारी मॉडल और सफल गठबंधन को जाता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को भी अपनी रणनीति और नेतृत्व पर गंभीर आत्ममंथन करना होगा। अब

देखना यह है कि यह नई सरकार बिहार के रोजगार और विकास के वादों को कैसे पूरा करती है।

बहरहाल, बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का साक्षी बना। शपथ ग्रहण खास इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए है। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता हर बार भरोसा करती है? तो बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 20 साल से काबिज नीतीश कुमार सूबे की सियासत में एक ऐसा निर्विवाद चेहरा हैं जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके परिवार के किसी सदस्य पर भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में समझे को सत्ता की काजल की कोठरी में भी नीतीश कुमार की छवि एक बेदाग राजनेता की रही है, इसलिए बिहार की जनता 20 साल से उनके चेहरे पर भरोसा करती आई है। नीतीश कुमार पर आज तक किसी भी उद्योगपति से सांठ-गांठ का कोई आरोप नहीं लगा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार उस बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है जहां पर परिवारवाद की राजनीति हावी है। नीतीश भले ही 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो लेकिन उनके बेटे आज भी सक्रिय राजनीति से दूर है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के फैसले और उनके निर्णय में उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी भूमिका नहीं है। बता दें कि 2005 से लेकर 2025 तक बिहार के हर चुनाव किसी पार्टी या गठबंधन के दम पर नहीं बल्कि नीतीश के चेहरे के दम पर लड़ा गया है और बिहार ने नीतीश के चेहरे को चुना है। नीतीश भाजपा के साथ-साथ बीच में 17 महीने तक आरजेडी के साथ सत्ता में रहे लेकिन अपने चेहरे की विश्वसनीयता बना कर रखा। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब बिहार में अपराध का बोलबाला था जिसे जंगलराज कहा जाता था, इसके साथ बिहार उस वक्त जातीय संघर्ष की आग में जल रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल के शासन काल में धार्मिक या जातीय दंगे नहीं हुए। इसके साथ नीतीश कुमार कहते है कि वो दौर गुजर चुका है। इसके साथ यह भी दिलचस्प है कि अगर आज बिहार में 20 साल पहले के राजद शासन के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव होते हैं तो इसे नीतीश की कामयाबी माना जा सकता है। भरोसा बिहार का नीतीश पर और नीतीश का बिहार पर जो निवेश, रोजगार और पलायन जैसे भारी नाकामियों पर भी हर बार भारी पड़ता है क्योंकि सबको लगता है कि अगर सुधार आया भी तो नीतीश से ही संभव है। इसके साथ नीतीश कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने फैसले से देश को नई राह दिखाई है। उन्होंने साइकिल योजना, पंचायत चुनावों से लेकर सरकारी नौकरियों तक में महिलाओं को आरक्षण प्रतिशत में बिहार देश में सबसे आगे है। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए नगर ट्रांसफर किए वह गेमचेंजर साबित हुआ। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को कभी अकेले दम पर विधानसभा में बहुमत नहीं मिला। नीतीश कुमार को गठबंधन की सरकार

चलाने में महारत हासिल है। नीतीश की पार्टी को आज तक अकेले अपने दम बहुमत नहीं मिला लेकिन गठबंधन को अपनी शर्तों पर चलाने की अद्वितीय महारत हासिल है।

गौरतलब है कि वर्तमान बिहार को नीतीश कुमार के 'सुशासन' और प्रधानमंत्री मोदी के 'विकास' के नजरिए से देखें, तो यह तीन ध्रुवोंजाति, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर टिका है। बिहार की राजनीति में जाति एक अटल सत्य है। लालू प्रसाद यादव ने एमवाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण से सामाजिक न्याय को चरम पर पहुंचाया। वहीं, नीतीश कुमार ने ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) और महादलितों को जोड़कर अपना आधार मजबूत किया। 2023 के जाति-आधारित सर्वेक्षण ने ओबीसी (27.12%) और ईबीसी (36.01%) की बड़ी आबादी को उजागर किया, जो कुल 63.13% है। यादव ओबीसी में सबसे बड़ा समूह हैं। राजनीतिक दल इसे जरूरी नीतियों का आधार बता रहे हैं। लेकिन आलोचक इसे चुनावी गठजोड़ मजबूत करने का हथियार मानते हैं। यह सर्वेक्षण नीतियों को दिशा दे सकता है, यदि सच्ची प्रतिबद्धता हो। बुद्ध के समृद्ध मगध से आज बिहार आर्थिक मानदंडों पर पिछड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति आय 69,321 रूपये (2024-25) है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.7 लाख रूपये से अधिक। रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश में कमी है। कृषि के अलावा कोई बड़ी आर्थिक गतिविधि नहीं। राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी युवाओं का पलायन है। 2025 तक लगभग 3 करोड़ बिहारी अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार, 74.54 लाख प्रवासी थे उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर। बेहतर शिक्षा और नौकरियों की तलाश में युवा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का रुख करते हैं। नीतीश सरकार ने 'सुशासन' के तहत सड़कें, बिजली और आधारभूत संरचना पर जोर दिया। बिजली कवरेज अब 99% तक पहुंच चुका है। लेकिन औद्योगिक विकास धीमा है। मोदी के 'विकास' मॉडल से निवेश आकर्षित करने की कोशिश जारी है, फिर भी पलायन रुकना बाकी है। बिहार में चुनाव हमेशा जातीय वफादारी और गठजोड़ पर निर्भर रहते हैं। आरजेडी का एमवाई संयोजन या एनडीए का सामाजिक संतुलन, जीत इन्हीं से आती है। लेकिन 2025 में विपक्ष की हार एमवाई समीकरण की कमजोरी से हुई। तेजस्वी की अपील युवाओं तक सीमित रही, जबकि एनडीए ने ईबीसी और महिलाओं को साधा। उदाहरण स्वरूप, पटना की एक रैली में तेजस्वी ने बेरोजगारी पर चुटकी ली, लेकिन मतदाताओं ने स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही शराबबंदी ने महिलाओं को सशक्त बनाया। 2025 चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा, जो एनडीए की जीत का प्रमुख कारक बना। नीतीश के फैसलों, जैसे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण और कैश बेनिफिट स्कीम ने उनकी छवि सामाजिक सुधारक की बनी रही। बता दें कि राजनीति अब विकास (मोदी फैक्टर) और सामाजिक न्याय (जाति-नीतियां) के बीच संतुलन खोज रही है। क्या मोदी का उद्योग-केंद्रित मॉडल बिहार की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है? नीतीश ने बुनियादी सुधार किए, लेकिन जाति के गणित से ऊपर उठकर आर्थिक गुणनफल पर फोकस जरूरी है।

बहरहाल, गौतम बुद्ध के विहारों से आज के राजनीतिक केंद्र तक, बिहार ने ज्ञान और सत्ता के उत्थान-पतन देखे हैं। आज यह दोराहे पर है। एक ओर जातिगत बेड़ियां और आर्थिक पिछड़ापन, दूसरी ओर सुशासन व विकास की आकांक्षाएं। नीतीश-मोदी नेतृत्व में बुनियादी बदलाव हुए हैं, जैसे बिजली और सड़कों का विस्तार। लेकिन सच्ची प्रगति तभी संभव, जब राजनीति जाति से आगे बढ़े। यह राज्य जाति, बाहुबल और सुशासन के अंतर्विरोधों के बीच विकास और पलायन-मुक्ति चाहता है। प्राचीन गौरव की वापसी इसी संतुलन से होगी। ●

बिहार की राजनीति में नया अध्याय

नीतीश कुमार की दसवीं पारी और बदलते सत्ता-समीकरणों की कहानी

● मिथिलेश कुमार

बिहार की राजनीति ने 20 नवंबर 2025 को एक नया और दुर्लभ अध्याय दर्ज किया। पटना के गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ ली, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता की वापसी का क्षण नहीं था बल्कि यह बिहार की राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक समीकरणों और शासन मॉडल को गहराई से समझने का अवसर भी था। एक ऐसे नेता की वापसी, जो दो दशकों से अधिक समय से राज्य की राजनीति में केंद्र में रहे, फिर भी हर बार नये ढंग से परिस्थितियों को साधते हुए स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। यह पारी किन राजनीतिक आधारों पर टिकी है, नया मंत्रिमंडल किस दिशा का संकेत देता है, और बिहार के सामने कौन-सी चुनौतियाँ और संभावनाएँ मौजूद हैं।

❖ **नीतीश कुमार : निरंतरता और परिवर्तन के बीच खड़ा एक नेता :-** भारतीय राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो लगातार बदलते गठबंधन, सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच स्वयं को टिकाए रखने की क्षमता रखते हों। नीतीश कुमार उनमें सबसे प्रमुख हैं। 2000 में सिर्फ सात दिनों की पहली पारी से लेकर 2025 की दसवीं पारी तक उनका सफर महज सत्ता की बात नहीं है यह रणनीति, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता का मिश्रण है। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश रहा है जनवर्गों का विश्वास। खासकर महिलाओं, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित और ग्रामीण तबकों में उनकी नीतियों ने गहरी पैठ बनाई। "सुशासन" का नारा कभी सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहा, बल्कि इसे उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून-व्यवस्था के माध्यम से जमीन पर उतरने की कोशिश भी की। यही कारण है कि लंबे शासन से अक्सर पैदा होने वाली एंटी-इंकबेंसी के विपरीत बिहार में एक तरह की प्रो-इंकबेंसी लहर देखी गई।

❖ **प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर एक राजनीतिक संदेश :-** शपथ समारोह की राजनीतिक भाषा बहुत कुछ कहती है। मंच पर छव। के तमाम चेहरे मौजूद थे, लेकिन केंद्र बिंदु नीतीश ही थे। यह संदेश स्पष्ट था कि बिहार राजनीति में अभी भी नीतीश का वजन किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि पूरे गठबंधन ढांचे से भारी है। दसवीं बार मुख्यमंत्री बनना केवल एक

राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनता के बड़े हिस्से ने स्थिरता, अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता दी। यह बिहार की राजनीतिक सोच में बदलाव की ओर इशारा करता है, जहाँ सिर्फ जातीय पहचान ही निर्णायक फैक्टर नहीं रह गया है।

❖ **गठबंधन का गणित: मंत्रिमंडल में संतुलन का खेल :-** नई सरकार का मंत्रिमंडल गठबंधन राजनीति का एक संतुलित चित्र है। जेडीयू और बीजेपी को लगभग बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। सहयोगी दलों को भी उनकी ताकत और योगदान के अनुरूप सीटें मिली हैं। युवा नेताओं और अनुभवी चेहरों के मिश्रण से संकेत मिलता है कि सरकार चुनावी तैयारी के साथ-साथ प्रशासनिक स्थिरता भी चाहती है। नीतीश कुमार के लिए हमेशा से मंत्रिमंडल केवल शक्ति-वितरण का मंच नहीं रहा है, बल्कि यह संदेश देने का माध्यम भी रहा है कि वह हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस बार भी उन्होंने जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को वरीयता दी है।

❖ **विकास मॉडल : नीतीश की राजनीति की रीढ़ :-** यदि बिहार में पिछले 20 वर्षों को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक आधार मुख्य रूप से विकास और सुशासन की नीतियों पर टिका है। कुछ मुख्य स्तंभ जिन्होंने उनकी लोकप्रियता को बनाए रखा :-

☞ **सड़क और बिजली क्रांति :-** गाँव-गाँव तक सड़कें और चौबीस घंटे बिजली व्यवस्था ने बिहार की छवि को बदला। लंबे समय तक अंधेरे में डूबे रहने वाले ग्रामीण इलाकों ने इस परिवर्तन को गहराई से महसूस किया।

☞ **महिलाओं का सशक्तिकरण :-** साइकिल योजना, पोशाक योजना, आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। इन सबने महिला मतदाताओं को नीतीश के प्रति मजबूत झुकाव दिया।

☞ **सामाजिक न्याय का नया ढांचा :-** पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व देने में वे सबसे सक्रिय रहे। यह नीति सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी; यह सामाजिक संरचना में बदलाव की कोशिश भी थी।

☞ **शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान :-** हालाँकि इन क्षेत्रों में चुनौतियाँ आज भी हैं, लेकिन नींव मजबूत करने का प्रयास हमेशा दिखा है।

❖ **राजनीतिक आलोचनाएँ: जो इस पारी का असली परीक्षण होंगी :-** नीतीश की लंबी पारी जितनी प्रशंसा लाती है, उतनी ही आलोचनाएँ भी।

☞ **बार-बार गठबंधन बदलने की छवि :-** कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह उनका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू रहा है। हालाँकि यह रणनीतिक लचीलापन है, लेकिन आलोचक इसे "अविश्वसनीयता" के रूप में भी देखते हैं।

☞ **युवाओं में बढ़ती नाराजगी :-** रोजगार, परीक्षा प्रणाली और पलायन जैसे मुद्दे उनकी सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। 2025 के चुनावों में भी युवाओं ने इन मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई।

☞ **प्रशासन का स्वरूप :-** भ्रष्टाचार, पुलिस-प्रशासन में ढिलाई और स्थानीय स्तर पर मनमानी की शिकायतें समय-समय पर आती रही हैं। दसवीं पारी में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह प्रशासनिक मशीनरी को फिर से चुस्त बनायें।

❖ **शपथ ग्रहण के राजनीतिक संकेत: बिहार किस दिशा में? :-** नीतीश कुमार की दसवीं पारी में तीन स्पष्ट संकेत उभरते हैं :-

☞ **स्थिरता की पुनः स्थापना :-** राज्य को राजनीतिक अस्थिरता के दौर से उठाकर एक बड़ी स्थिरता का संदेश दिया गया है। यह निवेश, उद्योग और रोजगार की कोशिशों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है।

☞ **एनडीए में नीतीश की केंद्रीय भूमिका :-** राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश की भूमिका अब और मजबूत होगी। एनडीए के भीतर वे सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तंभ के रूप में उभरे हैं।

☞ **बिहार मॉडल का विस्तार :-** सुशासन,

महिला-शक्ति और सामाजिक न्याय मॉडल को और गहरा करने की तैयारी दिखाई देती है। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस दिख सकता है।

❖ चुनौतियाँ :-

☞ **बेरोजगारी और कौशल विकास :-** राज्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है। जब तक बिहार में उद्योगिक ढाँचा नहीं खड़ा होता, तब तक पलायन कम होना मुश्किल है।

☞ **शिक्षा की गुणवत्ता :-** सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार एक सतत मुद्दा है। शिक्षा केवल भवन और पोशाक योजनाओं से नहीं सुधरेगी-गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही आवश्यक है।

☞ **कानून व्यवस्था :-** हालाँकि पिछले दशक में सुधार हुआ है, लेकिन अपराध की घटनाएँ अब भी राजनीतिक सवाल बनती हैं।

☞ **गठबंधन की आंतरिक राजनीति :-** नीतीश की ताकत यही है, लेकिन यही कमजोरी भी बन सकती है। गठबंधन का संतुलन बिगड़ा तो सरकार को झटके लग सकते हैं।

❖ **बिहार की राजनीति के बदलते चरित्र का प्रतीक :-** नीतीश कुमार की दसवीं पारी बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक और दिलचस्प क्षण है। यह उस बदलाव का संकेत है जहाँ जनता केवल पहचान की राजनीति नहीं देख रही, बल्कि स्थिरता, विकास, सुशासन और नेतृत्व अनुभवी व्यक्तित्व को प्राथमिकता दे रही है।इस पारी में नीतीश को न केवल अपनी स्थापित छवि को बनाए रखना होगा, बल्कि बिहार को तेज विकास और सामाजिक संतुलन के नए पथ पर ले जाना होगा। यदि वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह कार्यकाल बिहार के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसी घटना है जो एक साथ विस्मय और वितृष्णा दोनों पैदा करती है। यह आंकड़ा केवल सत्ता में उनकी वापसी का नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में व्याप्त उस गहरे शून्य का प्रतीक है, जिसे भरने में पक्ष और विपक्ष-दोनों नाकाम रहे हैं। राजनीतिक नैतिकता के चश्मे से देखें, तो बार-बार गठबंधन बदलना 'अवसरवाद' की श्रेणी में आता है, लेकिन शुद्ध 'सत्ता के गणित' के नजरिए से यह नीतीश कुमार की उस 'अपरिहार्यता' को दर्शाता है, जिसके आगे बड़ी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां भी नतमस्तक हैं। सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने फिर पाला क्यों बदला या उन्होंने 10वीं बार शपथ कैसे ली, प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चाहे 'कमल' हो या 'लालटेन', बिहार के सिंहासन का रास्ता 'तीर' के निशान से होकर ही गुजरता है? यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक नेता की ताजपोशी नहीं है, बल्कि यह बिहार में नेतृत्व के संकट और विचारधारा की राजनीति के अंत का एक सजीव दस्तावेज है। 10वीं बार ली गई यह शपथ बताती है कि बिहार में 'सरकारें' बदल सकती हैं, 'गठबंधन' बदल सकते हैं, लेकिन 'चेहरा' नहीं बदल सकता। क्या इसे नीतीश कुमार की 'सोशल इंजीनियरिंग' की जीत माना जाए या लोकतंत्र में नए विकल्पों के अभाव की हार? यह आलेख इसी विरोधाभास की पड़ताल करता है। आलेख के लिए प्रमुख बिंदु (Key Points for the Body): अंकगणित का जादूगर: कैसे घटती सीटों (जेडीयू के नंबर कम होने) के बावजूद नीतीश सीएम की कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं।विश्वसनीयता का संकट (Crisis of Credibility): क्या बार-बार पाला बदलने से उनकी 'सुशासन बाबू' वाली छवि धूमिल हुई है, या जनता ने इसे 'न्यू नॉर्मल' मान लिया है?●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

नीतीश का सुशासन मॉडल अब भाजपा की कसौटी पर

सम्राट चौधरी की बड़ी परीक्षा शुरू

● स्वदेश कुमार

बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही दसवीं बार पद पर आसीन हुए हैं, लेकिन असली सत्ता का केंद्र अब भाजपा के हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पटना में हाल ही में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 14 भाजपा और केवल 8 जेडीयू के प्रतिनिधि थे। यह संख्या-बदलाव सत्ता संतुलन में भाजपा की बढ़ती पकड़ को स्पष्ट करता है। मंच पर यह दृश्य साफ था कि अब सत्ता का असली असर भाजपा के हाथ में है। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब गृह मंत्रालय, जिसे नीतीश कुमार ने पिछले लगभग 20 साल तक स्वयं संभाला, अब भाजपा को सौंपा गया। डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब इस संवेदनशील विभाग के प्रमुख हैं। गृह मंत्रालय का नियंत्रण केवल पुलिस और कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब राज्य में अपराध नियंत्रण, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और सुरक्षा मामलों में भाजपा का सीधा प्रभाव रहेगा। सम्राट चौधरी का राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक और निर्णायक माना जाता है। उनकी चुनौती यह होगी कि वे नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन के मानकों को बनाए रखें। नीतीश ने अपने कार्यकाल में अपराध पर सख्ती, फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना और पुलिस को स्वतंत्र कार्रवाई की सुविधा देकर जनता में विश्वास पैदा किया था। अब यही जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर आ गई है। जनता की अपेक्षाएँ ऊँची हैं और हर बड़ी घटना के बाद उनकी तुलना नीतीश के साथ होगी।

पुलिस प्रणाली और प्रशासनिक तालमेल भी उनकी परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नीतीश के समय अफसरशाही को यह विश्वास था कि शीर्ष नेतृत्व सीधे कानून-व्यवस्था पर नजर रखता है। अब सम्राट चौधरी को यह भरोसा बनाए रखना होगा कि पुलिस निष्पक्ष और सशक्त है। बड़े मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई उनके नेतृत्व की परीक्षा होगी भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। बिहार में गृह मंत्रालय की पकड़ के साथ पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रही है। सम्राट चौधरी की जातीय पृष्ठभूमि, उनकी कुशवाहा जाति, पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में रणनीतिक लाभ भी दे सकती है। बिहार में उनके प्रभाव का विस्तार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल और 2029 लोकसभा

चुनाव की रणनीति से जुड़ा है।जेडीयू और भाजपा के बीच सत्ता संतुलन अब स्पष्ट रूप से भाजपा की ओर झुका है। मंत्रिमंडल में भाजपा ने 9 नए चेहरों को शामिल किया और केवल 5 पुराने मंत्रियों को पुनः स्थान दिया। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत है। जेडीयू को वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे विभाग मिले हैं, जो नौकरशाही और राज्य नीति के संचालन में अहम हैं, लेकिन असली शक्ति अब गृह मंत्रालय में केंद्रित है। आने वाली चुनौतियाँ सम्राट चौधरी के लिए बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि जनता और मीडिया उनकी तुलना नीतीश कुमार से करेंगी। हर बड़ी घटना पर यह सवाल उठेगा कि अगर नीतीश होते तो क्या होता। दूसरी चुनौती पुलिस प्रणाली और अफसरशाही के भरोसे को बनाए रखना है। नीतीश ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया था कि पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई करे। अब सम्राट को यह भरोसा बनाए रखना होगा। तीसरी चुनौती भाजपा नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उनकी सफलता सीधे पार्टी की साख और भविष्य की रणनीतियों से जुड़ी होगी। चौथी चुनौती एनडीए में संतुलन बनाए रखना है। भाजपा, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के बीच कानून-व्यवस्था के मामले कभी भी विवाद का कारण बन सकते हैं। पांचवीं चुनौती सोशल मीडिया और मीडिया दबाव है। हर घटना तुरंत वायरल होगी और राजनीतिक हथियार बन सकती है। छठी चुनौती नई पहचान बनाना है। नीतीश के मॉडल को अपनाते हुए सम्राट को अपनी अलग छवि बनानी होगी। सातवीं चुनौती जातीय और सामाजिक तनाव पर नियंत्रण रखना है। बिहार में छोटे विवाद बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं और पुलिस निष्पक्ष दिखनी चाहिए। आठवीं चुनौती जनता के भरोसे को बनाए रखना है। सुशासन की छवि कायम रखना और हर फैसले का जनहित में होना उनकी जिम्मेदारी होगी।

केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार अवैध घुसपैठ और सीमांचल की सुरक्षा प्राथमिकता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यह जिम्मेदारी भी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। सीमा पार की निगरानी, बीएसएफ और एनआईए के साथ तालमेल और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया उनके कार्यकाल में लागू होगी। भाजपा का लक्ष्य साफ है। बिहार में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा मामलों में केंद्र और राज्य का संयुक्त नियंत्रण स्थापित करना है। इसका मतलब है कि पुलिसिंग का स्वरूप बदलने वाला है। अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और राजनीतिक संतुलन मजबूत रहेगा। बुलडोजर और सख्त कार्रवाई के उदाहरण आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार अब उत्तर प्रदेश की राह पर बढ़ सकता है। भाजपा का इरादा है कि केंद्र और राज्य के समन्वय से कानून-व्यवस्था के नए मानक स्थापित किए जाएँ। यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने वाला कदम है।सम्राट चौधरी के लिए यह चुनौती है कि वे नीतीश के मॉडल को अपनाते हुए अपनी नेतृत्व छवि बनाएँ। जनता, मीडिया और राजनीतिक दल उनके हर कदम को मापेंगे। उनकी सफलता केवल गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बिहार में सुशासन, सामाजिक संतुलन और भाजपा की राजनीतिक साख में परिलक्षित होगी।

बिहार की राजनीति अब नए सिरे से परिभाषित हो रही है। गृह मंत्रालय भाजपा के नियंत्रण में आने से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में अपराध नियंत्रण, जातीय-सामाजिक संतुलन और राजनीतिक शक्ति का नया समीकरण बन गया है। आने वाले समय में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन और सियासत दोनों में नए मानक स्थापित होंगे। यदि वे इस चुनौती में सफल रहते हैं, तो बिहार में उनका प्रभाव नीतीश कुमार की छाया से आगे बढ़कर नए राजनीतिक समीकरण बनाएगा। उनकी भूमिका केवल गृह मंत्री की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में स्थायी और निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में होगी। जनता की निगाहें अब उनके हर कदम पर हैं और उनके फैसले तय करेंगे कि बिहार का 'सुशासन मॉडल' कितना स्थायी और प्रभावशाली रहेगा। ●

आतंकी डॉक्टरों ने दहलायी दिल्ली

● संजय कुमार सिन्हा

10 नवंबर, 2025 सोमवार को लालकीला के सामने पढ़े लिखे डाक्टरों ने एक साजिश के तहत अमोनिया नाईट्रेट विस्फोट किया और उनके मकसद सिर्फ लोगों को मारना सरकार को बदनाम करना देश को अस्थिर करना उनकी योजना थी, अब जो सामने बातें खुलकर आ रही है वो तो बहुत डरावनी और खतरे से भरी हुई है,अगर देश के युवा जो अपने को मुसलमान कह कर ऐसी घिनौनी कायराना हरकत इसे हरकत कहना गलत होगी इसे घिनौनी जघन्य अपराध ही कहेगें ऐसी घटना हरकत कभी नहीं हो सकती हैं, बम धमाके अगर रोड के विपरीत दिशा में होती तो मरने वालों और हताहत होने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा होती अभी मरने वालों की सरकारी संख्या 15 बताई जा रहीं हैं जबकि प्रत्यक्षदर्शियों मानना इससे कहीं बहुत ज्यादा हैं, धमाके के समय विस्फोट वाली आई टूवैन्टी कार के आगे और पीछे एक दर्जन गाड़ियों के परखचे उड़ गये और लोगों की शरीर 50 फीट उपर तक उड़ गई थी किसी के पैर पेड़ पर लटक रही थी तो

किसी के चिथड़े किसी मकान दूकान पर लटक रही थी सबसे नजदीक जैन मंदिर के पास भी शरीर के अंग लटके हुए पाये गये। नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी उमर मोहम्मद ब्लास्ट से पहले बम असेंबल करने के लिए हाई-इम्पैक्ट जगह की तलाश कर रहा था। धमाके में सुरक्षा एजेंसियों की जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद ने लाल किला की कार पार्किंग में ही बम को असेंबल किया था और करीब 3 घंटे तक वहां रुका रहा। इस दौरान वह अपने हैंडलर से लगातार फोन पर संपर्क में था और ब्लास्ट की जगह को फाइनल कर रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, उमर किसी "सिम्बॉलिक और हाई-इम्पैक्ट" लोकेशन की तलाश में था, जहां धमाके का ज्यादा असर हो। पहले उसका प्लान लाल किला की पार्किंग में ही ब्लास्ट करने का था, लेकिन सोमवार होने की वजह से वहां भीड़ कम थी, इसलिए उसने पार्किंग से बाहर निकलकर मेट्रो स्टेशन गेट-1 के पास ध माका कर दिया। इस आतंकी हमले में अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जांच एजेंसियां फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सहित देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। विश्वविद्यालय के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार

कर चुका है, साकेत कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। जावेद अब 1 दिसंबर तक ईडी हिरासत में रहेंगा। सहारनपुर से भी एमबीबीएस के छात्र को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहारनपुर के देवबंद में छापा मारकर एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस छात्र की आतंकी डाक्टर उमर मोहम्मद से फोन पर लगातार बातचीत हुई थी और इस मामले में पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि उमर को किस तरह की सपोर्ट सिस्टम मिल रही थी, उसके हैंडलर कौन थे और फंडिंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी से दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस हमले को लेकर एक पाक नेता ने पाकिस्तान की भागीदारी की बात कबूली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक पाकिस्तानी राजनेता ने दावा किया है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट में उनके देश की सीधी भूमिका थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने विधानसभा में कहा, ''मैंने पहले ही कहा था अगर तुम (भारत) बलूचिस्तान को लहूलुहान करते रहोगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें मारेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हमने ये कर दिखाया है, हमारे बहादुर जवानों ने ये कर दिखाया।'' भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले के बाहर विस्फोट की गई कार और इस साजिश के पीछे के आतंकवादी गिरोह का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है।

विस्फोट की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार 10 सदस्यीय 'आतंकवादी डॉक्टर' सेल की स्थापना जम्मू-कश्मीर के शोपियां के एक इस्लामी मौलवी इरफान अहमद ने की थी। मौलवी का जैश से सीधा संबंध था; वह कथित तौर पर मॉड्यूल के सदस्यों को जैश के आतंकवादियों से मिलने के लिए दक्षिण कश्मीर भी ले गया था, खुफिया एजेंसियों के अनुसार अहमद और एक पाकिस्तानी आतंकवादी उमर-बिन-खत्ताब उर्फ हंजुल्लाह इस गिरोह का संचालक था। अहमद ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पहचान की और उन्हें अपने खौफनाक विचारों से प्रभावित किया, जिनमें डॉ. उमर मोहम्मद भी शामिल था। अहमद सहित इस गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश के पास पहले से ही एक 'महिला ब्रिगेड' है, जिसे जमात उल-मुमिनात कहा जाता है। आतंकी सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया को उस यूनिट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। लाल किला विस्फोट के प्रमुख संदिग्धों में से एक डॉ. शाहिना सईद पर भी इसी विंग की सदस्य होने का आरोप है।●

पंचायत चुनाव में सीधे कूदने का साहस नहीं जुटा पा रही है सपा

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी की है, जिसने प्रदेश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। पार्टी सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में अपने अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यह निर्णय फिलहाल आंतरिक चर्चा के चरण में है, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट हैं कि पार्टी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर सीधा दखल देने से फिलहाल बचना चाहती है। यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। जिस तरह पिछले कुछ चुनावों में स्थानीय स्तर पर दावेदारी को लेकर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद बढ़े थे, उस स्थिति को दोबारा जन्म देने का जोखिम पार्टी नेतृत्व नहीं लेना चाहता। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यदि पंचायत चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी के पक्ष में गये तो 2027 के चुनाव की तैयारी में पूरे मनोबल से लगे समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनोबल भी कम होगा। इसी लिये सपा ने पंचायत चुनाव से प्रत्यक्ष तौर पर दूरी का मन बना लिया है।

सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की उच्च स्तर की बैठक में इस बात पर गंभीर मंथन हुआ है कि पंचायत चुनाव जैसे अर्धराजनीतिक निर्वाचन में अधिकृत उम्मीदवारों को उतारने से पार्टी का संगठन किस तरह प्रभावित हो सकता है। कई जिलों में पिछली बार यह देखा गया था कि टिकट वितरण और सहयोगी गुटों के बीच खींचतान ने पूरे संगठन को दो खेमों में बांट दिया था। नतीजा यह हुआ कि कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ गई। इस बार पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य है कि किसी तरह संगठनात्मक एकता को बनाए रखते हुए 2027 के चुनाव तक तैयारियां सुचारू रूप से जारी रहें। ऐसे में पंचायत चुनाव के स्तर पर किसी तरह का आंतरिक संघर्ष पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनावों में स्थानीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव ज्यादा अहम होते हैं। अधिकांश स्थानों पर उम्मीदवारों का चयन जातीय व सामाजिक समीकरणों के हिसाब से होता है, न कि सीधे-सीधे किसी दल के प्रतीक अथवा नीतियों के आधार पर। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी अपने झंडे और निशान के साथ प्रत्याशी उतारती है, तो स्थानीय मतदाताओं में दलगत छवि को लेकर भ्रम या विरोधाभास की स्थिति बन सकती है। पार्टी चाहती है कि उसके समर्थक और कार्यकर्ता इन चुनावों में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लें, लेकिन समाजवादी विचारधारा के अनुरूप लोगों को समर्थन दिया जाए। इसे अप्रत्यक्ष चुनावी भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति अखिलेश यादव की गहरी सोची-समझी चाल है। यूपी में

स्थानीय राजनीति का प्रभाव विधानसभा स्तर की राजनीति पर दिखता है। जब पंचायत चुनावों के नतीजे सामने आते हैं, तो उनसे यह आकलन लगाया जाता है कि किस पार्टी का वोट बैंक जमीनी स्तर पर मजबूत है। समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद वह उनकी समीक्षा कर एक ठोस रणनीति तैयार करे। इससे उसे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन जिलों और ब्लॉकों में जनता का रुझान उसके पक्ष में है, और कहां संगठन को मजबूती की जरूरत है। यानी यह कह सकते हैं कि पार्टी इन चुनावों को ''घोषित रूप से नहीं'' पर ''रणनीतिक सर्वेक्षण'' के रूप में ले रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछली बार पंचायत चुनावों में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच टिकट की होड़ और समूहबाजी ने कई जिलों में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया था। खासतौर पर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में इस तरह की तनातनी ने विधानसभा क्षेत्रों में कई जगह नतीजों को प्रभावित किया। इस बार पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़े और वह 2027 के मिशन को प्रभावित कर दे। इसलिए यह साफ हो गया है कि पार्टी अधिकारिक बयान भले न जारी करे, पर अंदरूनी रूप से फिलहाल पंचायत चुनाव में चुप रहना ही उचित समझ रही है।कई पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि यह कदम समाजवादी पार्टी की वर्तमान हालात में व्यावहारिक मजबूरी भी है। पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। संगठन को फिर से खड़ा करने की दिशा में अभी कई स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे वक्त पर अगर पंचायत स्तर पर गुटबाजी बढ़ी तो संगठनात्मक एकता पर गहरा असर पड़ेगा। नेतृत्व इस जोखिम को उठाने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव स्वयं कई बार सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि

आने वाला विधानसभा चुनाव पार्टी के अस्तित्व और भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए वे तमाम आंतरिक विवादों को पहले ही रोकने की कोशिश में हैं। पंचायत चुनाव में सीधे दखल न देना, इसी सोच की एक झलक माना जा रहा है।

हालांकि, इस रणनीति से कुछ स्थानीय नेताओं में असंतोष भी देखने को मिल सकता है। पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए अपने राजनीतिक कौशल को दिखाने और जनता के बीच पहुंच बनाने का मौका होता है। यदि पार्टी स्तर पर उन्हें अधिकृत समर्थन नहीं मिलेगा, तो कई महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकते हैं। इससे पार्टी के लिए यह चुनौती खड़ी होगी कि वह कैसे इन स्थानीय नेताओं को अनुशासित ढंग से संगठन से जोड़े रखे। पार्टी की योजना है कि पंचायत चुनाव के पूरा होने के बाद जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर फीडबैक लिया जाए और नई रणनीति तैयार की जाए। इससे पार्टी को 2027 से पहले नए नेतृत्व और कार्यकर्ता संरचना को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विपक्षी दल इस निर्णय को लेकर पहले ही अपने-अपने तरीके से टिप्पणियाँ

करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच अपनी कमजोर स्थिति से वाकिफ है, इसलिए वह हार के डर से मैदान छोड़ रही है। वहीं, बसपा और कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सपा नेतृत्व इस बहाने अपने आंतरिक मतभेदों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सपा के सूत्र इसे रणनीति बताते हैं और कहते हैं कि पंचायत चुनाव में जो समर्थक सपा के विचारों से जुड़े होंगे, वे स्वाभाविक रूप से पार्टी के साथ रहेंगे, भले ही उम्मीदवारों का नाम औपचारिक रूप से घोषित न किया जाए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह कदम सपा के लिए एक 'डैमेज कंट्रोल' की तरह है। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी नेतृत्व चाह रहा है कि पंचायत चुनावों से पहले किसी गठबंधन या साझा रणनीति की चर्चा शुरू न हो, ताकि स्थानीय स्तर पर पार्टी के स्वतंत्र संगठनात्मक ढांचे को बचाया जा सके। संभव है कि पंचायत चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने के बाद पार्टी संभावित सहयोगी दलों के साथ अपनी नई राजनीतिक दिशा स्पष्ट करे। इस तरह यह निर्णय केवल पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि 2027 के बड़े संघर्ष की तैयारी का हिस्सा है। बहरहाल, अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, परन्तु पार्टी सूत्रों की मानें तो जल्द ही प्रदेश संगठन के भीतर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यदि यह निर्णय वास्तविक रूप से लागू होता है, तो पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी पहली बार इस तरह से 'अप्रत्यक्ष' भूमिका निभाएगी। यह प्रयोग यूपी की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने वाला साबित हो सकता हैकृकि कभी-कभी चुनाव में सक्रिय भागीदारी से अधिक प्रभावशाली होता है समयानुकूल संयम और रणनीतिक मौन। ●

टकराव के बाद योगी की आजम पर मेहरबानी

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से कई बार विधायक व सांसद रह चुके आजम खान का नाम बीते चार-पांच साल से अधिकतर विवादों और कानूनी मामलों में ही सुर्खियों में रहा है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के दौरान आजम खान पर जमीन कब्जे से लेकर फर्जी दस्तावेज, भैंस चोरी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे जैसे कई आरोप लगे, जिनमें वे एक-एक कर जेल भी गए। उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए और उनकी राजनीतिक हैसियत को झटका देने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब हालात अचानक बदले हैं। पहले अदालत से उन्हें जमानत मिलती है, फिर योगी सरकार उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर देती है। सत्ता के गलियारों से लेकर विश्लेषकों के बीच सवाल यही है कि यह बदलाव सरकार के रवैये में अचानक क्यों आया और इसके पीछे छिपा संदेश क्या है।

राजनीतिक जानकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि योगी सरकार का यह रुख सिर्फ कानून के अनुपालन का मामला नहीं है, बल्कि यह कहीं न कहीं आने वाले चुनावी समीकरण का हिस्सा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा प्रतिशत है और सपा लंबे समय से इस वोट बैंक की राजनीति का केंद्र रही है। आजम खान, भले ही तमाम मामलों के चलते कमजोर पड़े हों, लेकिन रामपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ अब भी है। ऐसे में यह मानना गलत नहीं होगा कि आजम खान को राहत देकर सरकार एक तरह से यह संकेत दे रही है कि वह टकराव की राजनीति से हटकर संवाद और सहमति के रास्ते पर भी चल सकती है। यह रणनीति विशेषकर तब अहम हो जाती है जब सत्तारूढ़ पार्टी किसी खास वर्ग में अपनी साख सुधारने की कोशिश में हो। दूसरी तरफ, यह कदम सपा के अंदर भी हलचल का कारण बना है। अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में खटास की खबरें आती रही हैं। आजम को लगता रहा कि उन्हें पार्टी ने उनके बुरे वक्त में पूरी ताकत से बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि अखिलेश यह समझते रहे कि उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोप पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आजम खान के प्रति योगी सरकार का यह "सौम्य" रवैया सपा के भीतर एक तरह की बेचैनी पैदा कर सकता है और विपक्षी खेमों में अविश्वास की दरार बढ़ा सकता है। यह भी संभव है कि भाजपा को पता हो कि कमजोर पड़े आजम खान को सीधे-सीधे सत्ता के खिलाफ खड़ा करना अब कठिन है, लेकिन उनके साथ संबंधों को सहज रखकर समाजवादी पार्टी के भीतर दरार को और गहरा किया जा सकता है, जिससे विपक्षी एकजुटता कमजोर पड़े। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यह कदम किसी अदालती दबाव या सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर भी हो सकता है। आजम खान के ऊपर लगातार खतरे की आशंका जताई जाती रही है, खासकर रामपुर में उनकी राजनीतिक हैसियत और विवादित बयानों को देखते हुए। ऐसे में वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाली एक प्रशासनिक निर्णय भी हो सकता है। लेकिन राजनीति में संयोगों पर कम और संदेशों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसे केवल "सुरक्षा की जरूरत" के चश्मे से देखना अधूरा होगा।

प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में आजम खान की स्थिति खास है। भाजपा के लिए यह समुदाय पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मतदाता रहा है। भाजपा नेतृत्व को यह भलीभांति पता है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा एक झटके में नहीं जीता जा सकता, लेकिन एक वर्ग में सकारात्मक संदेश देकर और विपक्ष के भीतर असंतोष पैदा कर उसे बांटा जा सकता है। आजम खान को मिली इस राहत को भी उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। भाजपा के भीतर इस समय दो पैरेलल रणनीतियाँ दिख रही हैं एक तरफ हिंदुत्व के आक्रामक एजेंडे को बनाए रखना, दूसरी तरफ खास परिस्थितियों में कुछ मुस्लिम चेहरों के प्रति संवेदनशील रुख दिखाकर मुस्लिमों के प्रति सरकार के नम्र रवैये के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा की छवि को थोड़ी संतुलित दिखाने में मदद करता है। आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी भी तरह की सीधी नजदीकी की संभावना को अभी दूर की कौड़ी माना जा सकता है, लेकिन राजनीति में हित और परिस्थिति अक्सर पुराने संघर्षों को भी पिघला देते हैं। यह भी विचारणीय है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गई है। ऐसे में छोटे-छोटे संकेत, जैसे किसी विरोधी धड़े के प्रभावशाली नेता को राहत देना, आगे चलकर बड़े बदलावों के आधार बन सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भाजपा और आजम खान की राजनीति हमेशा परस्पर विरोधी रही है। रामपुर का उपचुनाव इसका ताजा उदाहरण था, जहां आजम खान के प्रभाव वाले इलाके में भाजपा ने जीत दर्ज की और यह नतीजा उनकी राजनीति पर चोट के रूप में देखा गया। मगर अब वही सरकार सुरक्षा वापस देती है तो संदेश यह जाता है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। यह भी ध्यान रखने लायक है कि कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष के किसी पुराने मजबूत नेता को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे सॉफ्ट कॉर्नर देकर सीमित असर वाले खेमे में बदलने की कोशिश करता है, जिससे वह दीर्घकाल में सत्ता के लिए खतरा न बने और विरोधी की एकजुटता भी टूटे।?

कुल मिलाकर, यह कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान को जमानत और सुरक्षा बहाली देने के पीछे कई परतों वाली रणनीति है। एक तरफ सरकार अपने कानून के शासन की इमेज को मजबूत कर सकती है कि जो भी खतरे में है, उसे सुरक्षा मिलेगी, दूसरी तरफ वह विपक्षी राजनीति के भीतर दरार और टकराव को बढ़ा सकती है। चुनावी लाभ, मुस्लिम समुदाय में नियंत्रित पहुंच, और विपक्ष के प्रभावशाली नेताओं को राजनीतिक तौर पर तटस्थ करने की नीति ये तीनों पहलू इस कदम की पृष्ठभूमि में नजर आते हैं। इसलिए इस घटनाक्रम को केवल एक प्रशासनिक निर्णय या अदालती प्रक्रिया का नतीजा मानना राजनीति की बारीकियों को नजरअंदाज करना होगा। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह एक संकेत है कि चुनावी सालों से पहले सत्ता पक्ष रणनीतिक चालें चलकर विपक्षी खेमे को असंतुलित करने में लगा है।●

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवा न केवल एक बुनियादी अधिकार है, बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी भी। बिहार, जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही संसाधनों की कमी, आधारभूत संरचना की जर्जरता और प्रशासनिक अक्षमताओं से जूझ रही है। ऐसे में, जब राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी-बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और जातीय घृणा फैलाने के गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन जाता है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता पर सवाल उठाता है। हाल के दस्तावेजों और शिकायतों से उजागर हुए ये आरोप श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS), BMSICL के प्रबंध निदेशक, के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ये आरोप न केवल व्यक्तिगत कदाचार के हैं, बल्कि वे बिहार की अस्मिता, गरीबों के स्वास्थ्य अधिकार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को छूते हैं। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी नौकरशाही अब भी 'जनसेवा' की भावना से प्रेरित है, या वह सत्ता के दुरुपयोग का माध्यम बन चुकी है।

बीएमएसआइसीएल के एमडी कोर्ट में हों हाजिर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम (बीएमएसआइसीएल) की ओर से दीपावली से लेकर छठ पूजा के बीच में औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए ई. निविदा आमंत्रित करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पश्चिमी) के कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसमें बीएमएसआईसीएल पटना के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश रामचंद्र देवड़े, प्रबंधक हरेंद्र राम और मुख्य प्रबंधक सप्लाई चेन की सीमा कुमारी को अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर को सदेह उपस्थित होने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार को मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र समर्पित कराने का निर्देश दिया गया है।

18 दिसंबर को सदेह हाजिर होने को कहा, मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक को भी उपस्थित होने का मिला आदेश

औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए दीपावली से छठ के बीच ई. निविदा आमंत्रित कराने को लेकर कोर्ट में दायर है परिवाद

गौरतलब है कि सदर थाना के लहलादपुर पताही निवासी सुधीर कुमार ओझा ने बीएमएसआइसीएल पटना के उक्त अधिकारियों पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद किया था। परिवाद में कहा कि 20 अक्टूबर को पूजा का सामान खरीदने के दौरान करजा के पकड़ी पकोही चौक रेवा रोड में आरोपित की ओर से निर्गत व आदेशित दो पत्र पढ़ा।

इसमें जानबुझकर बीएमएसआइसीएल की ओर से औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए ई. निविदा दीपावली से छठ के बीच आमंत्रित की गई थी। आरोप लगाया कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने व फर्जीवाड़ा करने व हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह तिथि निर्धारित की गई थी। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा।

भ्रष्टाचार अब केवल आर्थिक अपराध नहीं रहा, यह सामाजिक असमानता, जातीय विभाजन और प्रशासनिक अमानवीयता का स्रोत बन गया है। बिहार जैसे राज्य में, जहां स्वास्थ्य सेवा गरीबों का एकमात्र सहारा है, वहां दवाओं की कमी, उपकरणों की घटिया गुणवत्ता और अस्पतालों में अव्यवस्था सीधे जानलेवा साबित हो रही है। यह एक विडंबना है कि जिस संस्थान को स्वास्थ्य सुधार की उम्मीद के रूप में बनाया गया था, वही अब आम जनता के लिए पीड़ा का कारण बन गया है।

BMSICL के हालिया कार्यों में यह देखा गया कि निविदा प्रक्रिया को मनमाने ढंग से बदला गया ताकि कुछ कंपनियों को लाभ मिले। उदाहरण के लिए, निविदा संख्या BMSIC/DRUGS/25-12 में EMD जमा करने की अंतिम तिथि दीपावली के दिन रखी गई। त्योहार के कारण कई दवा कंपनियाँ बंद रहती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा घटती है और ऊँची दरों पर निविदाएँ पास होती हैं। इसी तरह, निविदा संख्या BMSICL/2023-24/ME-317 में मेडिकल वेस्ट स्टेरलाइजेशन उपकरणों की खरीद में कोरिजेंडम-1 जारी कर मूल शर्तें बदल दी गई, जिससे एक निजी कंपनी S.S. Medical Systems को अनुचित लाभ मिला। इससे राज्य को लगभग 75 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पारदर्शिता के नाम पर स्थापित यह संस्था अब 'कमीशन संस्कृति' की प्रयोगशाला बन चुकी है।

वर्तमान में बीएमएसआईसीएल के MD नीलेश रामचंद्र देवरे, मुख्य महाप्रबंधक आपूर्ति श्रृंखला कुमारी सीमा ने दिनांक-16/10/25 को S.S. Medical System (I) Pvt. Ltd को 84 करोड़ 11 लाख रुपए का क्रय आदेश निर्गत किया इसमें जीएसटी चार्ज अलग से है। इस पत्र के साथ संलग्न चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा की क्रय आदेश में बिहार के राज्य कोषागार को 75 करोड़ 90 लाख 37500 का नुकसान हुआ है और जीएसटी का नुकसान अलग से है, अगर अभी तक के क्रय आदेश को जोड़ लिया जाए तो कम से कम बिहार जैसे गरीब राज्य को

100 करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान हो चुका है। इस क्रय आदेश में मांग से अधिक का क्रय आदेश ही नहीं बनवाया गया, जरूरत से अधिक का कृत्रिम मांग भी बनवाया गया है।

श्री देवरे पर आरोप है कि उन्होंने BMSICL में जातीय गुटबाजी को बढ़ावा दिया। कुछ कर्मचारियों और सप्लायरों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए पदों का दुरुपयोग किया गया। ऐसी घटनाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत का उल्लंघन हैं। इससे सामाजिक असंतुलन और प्रशासनिक अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पहले से जातीय विभाजन की संवेदनशीलता है, ऐसे मामले समाज में और दरार पैदा करते हैं।

BMSICL के भीतर जातीय गुटबाजी और पक्षपात की जड़ें गहरी हैं। CGM (सप्लाई चेन) सुश्री सीमा कुमारी, असिस्टेंट मैनेजर नितिन कुमार जैसे लोगों के बीच असामान्य नजदीकी प्रशासनिक नैतिकता पर प्रश्न उठाती है। इन पर आरोप है कि फाइलें क्लियर करने के लिए कमीशन तय दरों पर लिया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल पर 0.5%, ड्रग फाइल पर 0.25% और इक्विपमेंट फाइल पर 1% तक। यह सब संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसी प्रवृत्तियाँ न केवल योग्य लोगों को हाशिये पर डालती हैं बल्कि समाज में यह संदेश देती हैं कि 'काबिलियत नहीं, संपर्क सफलता की कुंजी है।'

PMCH में कथित तौर पर दिए गए आपत्तिजनक वक्तव्य– "बिहारी साला चूतिया होता है" न केवल बिहार की अस्मिता का अपमान है बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचरण नियमों का भी उल्लंघन है।

Bihar Medical Service & Infrastructure Corp. Ltd
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura,
Adjacent to State Health Society,Patna-800014, Bihar

Firmwise Detailed Report
For category : All , Supplier : , Supplier PO Status : All
(From 15-Oct-2025 To 17-Oct-2025)

S. No.	PO No. & Date	Item Name	Programme Name	Rate/Unit	Inactive Qty.	% of Overall Supply	% of Unusable Supply	District	PO Qty. (No.)	PO Value (Rs.)	Total Recieved Qty (No.)	Total Recieved Value (Rs.)
Firm Name : S S Medical System India Pvt. Ltd.												
1	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	6250	96812500.00	0	0.00
2	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	6250	96812500.00	0	0.00
3	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	5000	77450000.00	0	0.00
4	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	7500	116175000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	25000.00	387250000.00	.00	.00
5	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	300000	20700000.00	0	0.00
6	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	200000	13800000.00	0	0.00
7	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	250000	17250000.00	0	0.00
8	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	250000	17250000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	1000000.00	69000000.00	.00	.00
9	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	300000	29400000.00	0	0.00
10	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	250000	24500000.00	0	0.00
11	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	250000	24500000.00	0	0.00
12	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	200000	19600000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	1000000.00	98000000.00	.00	.00
13	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	7500	86055000.00	0	0.00
14	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	5000	57370000.00	0	0.00
15	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	6250	71712500.00	0	0.00
16	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	6250	71712500.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	25000.00	286850000.00	.00	.00
								Firm Wise Group Total :	2050000.00	841100000.00	.00	.00
								Grand Total :	2050000.00	841100000.00	.00	.00

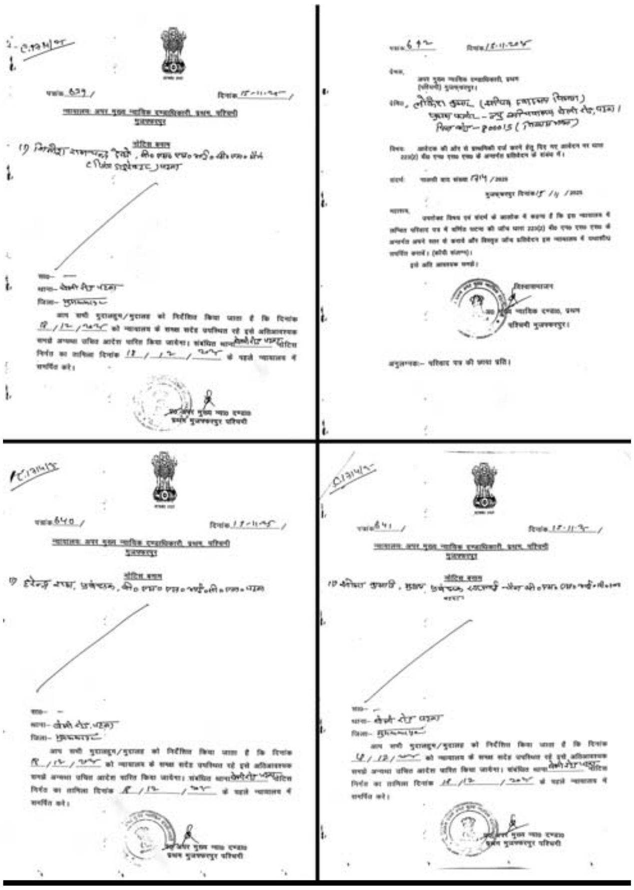

ऐसे वक्तव्य क्षेत्रीय घृणा और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। बिहार की धरती, जिसने डॉ. राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं को जन्म दिया, उनके आदर्शों पर यह चोट है।

श्री देवरे की संपत्ति घोषणा में भी अनियमितताएं पाई गईं हैं। जमीनों के वास्तविक मूल्य को कम दिखाया गया और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से सांठगांठ के आरोप लगे हैं। ऐसी हरकतें न केवल आर्थिक अपराध हैं बल्कि सामाजिक नैतिकता और पारदर्शिता की नींव को कमजोर करती हैं।

श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS) हमेशा ही विवादित आईएएस अधिकारी के रूप में रहे हैं, इनका व्यवहार बिहारी के प्रति हमेशा ही गलत रहा है वह जहां भी जिलाधिकारी के रूप में रहे हैं, वहां उन्होंने बिहारी अस्मिता और बिहारी को नुकसान पहुंचाया है। श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS) जिस पद पर रहे हैं भ्रष्टाचार के हर सीमा को उन्होंने तोड़ दिया है। श्री देवरे ने 2024-25 में जो अपना असेट्स डिक्लेरेशन दिया है उसमें भी कई त्रुटि है। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम Saee S लिखा है जो कि अपने आप में एक कहानी बयाँ करती है। पत्नी के नाम पर डिक्लेरेशन में लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी का कोई जॉइंट इनकम या प्रॉपर्टी नहीं है, यह नियम का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने अपने इमूवेबल एसेट में ग्राम-तामसवारी, जिला-धुले महाराष्ट्र और ग्राम-हारताली, जिला-सतना, महाराष्ट्र के जमीन का काम मार्केट वैल्यू दिखाया है। उनका जमीन का पूरा लीगल पेपर हम इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों जमीन के वर्तमान मार्केट प्राइस लगभग 15 लाख बताया है, जबकि इस जमीन का वास्तविक मार्केट प्राइस 4 करोड़ से भी ऊपर का है। इसलिए इनका असेट्स

COMPARATIVE CHART(BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL,COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL,COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL,BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL) BMSICL VALUE Vs MARKET PRICE

S. NO	PO No. & Date	Item Name	BMSICLRate/Unit	AVERAGE PRICE E	Budget Supplies Pvt. Ltd. B	MedEquip Traders	HealthTech Solutions Pvt. Ltd. C	ARV Supplies D	MARKET PRICE ExG	RWH	BMSICL ORDER Quantity (P.O.)G	PO VALUE (RS.)
	Firm Name : S S Medical System India Pvt. Ltd											
1	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	9687500	Bihata	6250	96812500
2	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	9687500	Muzaffarpur	6250	96812500
3	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	7750000	Purnia	5000	77450000
4	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	11625000	Patna	7500	116175000
							PO WISE GROUP TOTAL		38750000		25000	387250000
1	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1725000	Patna	300000	20700000
2	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1150000	Purnia	200000	13800000
3	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1437500	Muzaffarpur	250000	17250000
4	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1437500	Bihata	250000	17250000
							PO WISE GROUP TOTAL		5750000		1000000	69000000
1	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2550000	Patna	300000	29400000
2	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2125000	Bihata	250000	24500000
3	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2125000	Muzaffarpur	250000	24500000
4	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	1700000	Purnia	200000	19600000
							PO WISE GROUP TOTAL		8500000		1000000	98000000
1	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	8718750	Patna	7500	86055000
2	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	5812500	Purnia	5000	57370000
3	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	7265625	Muzaffarpur	6250	71712500
4	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	7265625	Bihata	6250	71712500
							PO WISE GROUP TOTAL		29062500		25000	286850000
							FIRM WISE GROUP TOTAL		82062500		2050000	841100000
							GRAND TOTAL		82062500		*2050000*	841100000

BMSICL TOTAL ORDER VALUE						Eighty Two Crore Sixty Two Thousand Five Hundred Only.				
84,11,00,000	WITHOUT GST							Eighty-four crore, eleven lakh Only.		
MARKET PRICE TOTAL VALUE										
82062500	WITHOUT GST									
DEFERANCE										
[redacted]	WITHOUT GST									
Seventy-five crore, ninety lakh, thirty-seven thousand, five hundred Only.										
Rupees:- 759037500.00 (Seventy Five Crore Ninety Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) SCAM										

डिक्लेरेशन पूरी तरह से फर्जी और गैरकानूनी है।

श्री देवरे ने 50 लख रुपए लेकर श्री बालाजी टेस्ट लैब को काली सूची में दर्ज नहीं किया जबकि NABL ने उसे 23 मार्च 2025 को उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। BMSICL के निविदा संख्या-BMSICL/QC/01/2023 के शर्त संख्या-18- (b) Proficiency testing of samples will be done on random basis in other laboratories or Govt- Laboratories of and any discrepancy of reports will be taken as nonperformance- For each such instance of nonperformance] no bills for performing the tests will be paid to the testing laboratory- For three such non performances in each year of the contract period] 25» of the security deposit will be deducted- For every subsequent nonperformance in each year 10» each of the security deposit will be deducted- If such non performances eñceed siñ during in each year of the contract period] the testing laboratory will be removed from the empanelment and black listed for a period of 2(two) years के अनुसार अगर 6 बैच का रिपोर्ट गवर्नमेंट लैब रिपोर्ट से नहीं मैच खाता है तो उसे नॉन परफॉर्मेंस कहा जाएगा। उसे अगले दो वर्षों के लिए Empanelment से हटा दिया जाएगा और नियम (c) If it is revealed that drug testing Laboratory is involved in any form of fraud and collusion with the suppliers of BMSICL, the drug testing laboratory will be blacklisted for Five (5) years के तहत 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। श्री बालाजी टेस्ट लैब का 30 से ज्यादा रिपोर्ट मिसमैच हुआ है और कंपनी ने APPLE फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड से पैसा नहीं मिलने के कारण उसका 35 बैच फेल कर दिया उसका भी प्रमाण इस पत्र के साथ संलग्न है। श्री बालाजी टेस्ट लैब ने APPLE फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड का कई बैच जानबूझकर फेल कर दिया और CDL ने उसे पास कर दिया जिससे उसका फ्रॉड साबित होता है, लेकिन श्री देवरे की कृपा होने के कारण श्री बालाजी टेस्ट लैब PVT. LTD. का बाल भी बांका नहीं हो सका।

बीएमएसआईसीएल के एमडी सहित तीन अधिकारियों को सदेह हाजिर होने का आदेश

दवा खरीद के लिए दिवाली के दिन टेंडर निकालने की होगी जांच

नोटिस जारी

- खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने को दिवाली के दिन ई-निविदा निकालने का आरोप
- परिवाद के आधार पर सीजेएम ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा पत्र
- अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में अक्टूबर में दाखिल किया था परिवाद

क्या है बीएनएनएस की धारा 223(2)

जब किसी सरकारी संस्थान व अधिकारियों पर न्यायालय में कोई आरोप लगाया जाता है तो कार्रवाई से पूर्व इस धारा के तहत संबंधित अधिकारी और उनके विभागाध्यक्ष का पक्ष लिया जाता है। यह कानून किसी भी सरकारी कर्मी को नाजायज मुकदमों से बचाने को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है। आरोपित अधिकारियों के जवाब और संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय कार्रवाई का निर्णय लेता है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दवा खरीद मामले में बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि. (बीएमएसआईसीएल) पर लगे आरोप की जांच स्वास्थ्य सचिव करेंगे। बीएमएसआईसीएल ने दिवाली के दिन करोड़ों रुपये की दवा खरीद का ई-टेंडर निकाला था। आरोप है कि खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए त्योहार के दिन टेंडर निकाला गया था।

मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने परिवाद की प्रति के साथ मामले की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने के लिए स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार को पत्र भेजा है। इसके साथ ही बीएमएसआईसीएल के एमडी निलेश रामचंद्र देवरे, प्रबंधन हरेंद्र राम और मुख्य प्रबंधक सप्लाई सीमा कुमारी को न्यायालय में 18 दिसंबर को सशरीर हाजिर रहने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस की ससमय तामिला का पटना के बेली रोड थानेदार को आदेश दिया गया है।

इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीते 29 अक्टूबर को न्यायालय में परिवाद दायर कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिवाली के दिन (20 अक्टूबर, 2025) को बीएमएसआईसीएल की ओर से बड़े पैमाने पर दवा खरीद के लिए ई-टेंडर जारी किया गया। जबकि दिवाली पर तमाम सरकारी कार्यालय ना केवल बंद रहता है, बल्कि तमाम लोग पर्व पर व्यस्त रहते हैं। इस तरह का टेंडर निकालने के पीछे मंशा किसी खास एजेंसी को लाभ पहुंचाना ही है। साथ ही इस टेंडर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सीजेएम कार्यालय से स्वास्थ्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि इस परिवाद में लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(2) के तहत जांच कर रिपोर्ट समर्पित करें। ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।

बीएमएसआईएल में खुद राज्य क्रय संगठन है। श्री देवरे ने

निलेश रामचंद्र देवरे

सी.आर. पाटिल

प्रत्यय अमृत

अपनी मनमानी करने के लिए की निविदा प्रकाशित की -NIT No.--BMSICL/INFRA/34/2025 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का परफॉर्मेंस सपोर्ट आफ मेडिकल इक्विपमेंट ऑफ बिहार जिसमें उन्होंने शर्त संख्या-20. 4, 20.5, 20.6 और 20.7 में ऐसी नियम शर्तें रखी हैं कि उनकी मनचाही कंपनी का ही सिलेक्शन इसमें हो पाए और उनकी मनमानी चलती रहे और निविदा में ज्यादा से ज्यादा कमीशन देने वाले को निविदा के लिए सिलेक्ट कर सकें और उनको क्रय आदेश दे सके।

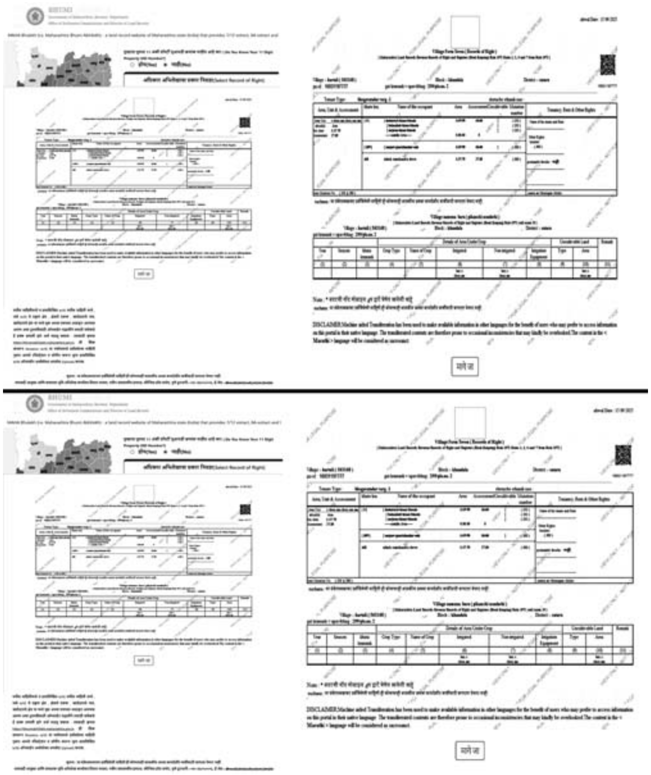

श्री देवरे का कहना है कि BMSICL निविदा संख्या -BMSIC/DRUGS/2022-24 जो QCBS सिस्टम में RODIAC कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और निविदा संख्या -BMSICL/ME-347-BMSICL /2024-25 ME-277 QCBS सिस्टम के तहत क्विक क्लीन प्राइवेट लिमिटेड को निविदा दिया गया यह दोनों कंपनी वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की कंपनी है अगर मेरे विरुद्ध जांच हुआ तो मैं भी इन दोनों कंपनियों का पेपर सारे विरोधियों को दे दूंगा और साथ ही मीडिया में बांट दूंगा। साथ ही ये बोलते हैं की हम देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री सी.आर. पाटिल के दामाद हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

BMSICL के प्रबंध निदेशक की संपत्ति घोषणा में भारी विसंगतियाँ पाई गई है। उन्होंने महाराष्ट्र स्थित संपत्तियों के मूल्य को कम बताया और अपनी पत्नी के नाम से संयुक्त संपत्तियों को छिपाया। साथ ही ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से सांठगांठ के आरोप लगे हैं, जिनके बदले कथित रूप से लाखों रुपये की रिश्वत ली गई। यह स्पष्ट संकेत है कि नौकरशाही में 'Conflict of Interest' की संस्कृति गहराई तक जड़ें जमा चुकी है।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है, यह सामाजिक कुरीतियों को जन्म देता है। जातिवाद, पक्षपात, और ब्यूरोक्रेटिक अहंकार जैसे तत्व प्रशासन को जनता से दूर कर देते हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में फैली यह सड़ांध गरीबों की मौत का कारण बन रही है। यह एक सामाजिक विडंबना है कि जिस राज्य ने समाज सुधार की मिसालें कायम कीं, वहीं आज भ्रष्टाचार और अनैतिकता की गिरफ्त में है।

सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. Kraipak vs Union of India (1969) और Tata Cellular vs Union of India (1994) के मामलों में यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक निर्णय 'Fairness in Action' के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। BMSICL की घटनाएँ इन सिद्धांतों के उल्लंघन का उदाहरण हैं। साथ ही, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 38 (राज्य की सामाजिक न्याय नीति) इन सभी घटनाओं से प्रभावित होते हैं।

BMSICL के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। CBI, Vigilance या ED जैसी एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच इस समय की आवश्यकता है। साथ ही, हमें सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-टेंडरिंग, थर्ड-पार्टी ऑडिट और जनता की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा। समाज को भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि चुप रहना भी अपराध है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत, जयप्रकाश नारायण की 'संपूर्ण क्रांति' हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की मशाल हमारे भीतर से ही जलती है।●

न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये साइबर अपराधी

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

साइबर थाना पटना के डीएसपी नीतीश चन्द्रधारिया के नेतृत्व में बीते दिनों गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। एस.टी.एफ. एवं शास्त्रीनगर थाना के सहयोग से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि खाजपुरा बेली रोड, पीलर नं.-21 के समीप मात्री होटल एवं बैंकेट में कुछ अंतरराज्यीय साइबर अपराधी जुटे हुये हैं, जो किसी गंभीर साइबर अपराध करने हेतु आये हुए हैं। शास्त्रीनगर थाना के सहयोग से उक्त होटल से कुल 13 व्यक्तियों को कब्जे में लेकर पूछताछ किया गया तथा उनके पास से बरामद मोबाईल का जाँच करने में पर मोबाईल में कई संदिग्ध एकाउंट नम्बर पाया गया। सभी संदिग्ध एकाउंट नं. का तकनीकी जाँच एन.सी.आर.पी. पोर्टल के मदद से किया गया तो पाया गया कि विभिन्न एकाउंट पर भारत के कई राज्यों से करीब 40 शिकायत दर्ज पाया गया है, जो कुल 14, 10, 36, 261 रूपये का वित्तीय साइबर ठगी है। इन सभी व्यक्तियों का टेलीग्राम पर टास्क देने, ऑनलाईन जॉब देने एवं बीटक्वाइन में इन्भेस्टमेंट करने के नाम पर, माईक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर तथा गेमिंग के नाम पर लोगों से साइबर ठगी किया करते थे। इनके अतिरिक्त इनके गिरोह में अन्य एक व्यक्ति की भी संलिप्तता पायी गयी है। गिरफ्तार सभी 13 अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जब्त सामानों में 15 मोबाइल और 1 स्वीफ्ट डीजायर कार बरामद किया गया है। पटना साइबर थाना कांड सं. -2143/25 के अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोपालपुर थाना अंतर्गत बेईमान टोला

कनौली स्थित प्रियंका सिंह के मकान में साइबर ठग रहकर साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिनके द्वारा बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर के नाम पर, गैस स्टोव रिपेयरिंग सेंटर के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर एवं अन्य वेबसाईट बनाकर लोगों से ठगी किया करते थे। इस कार्य में इनके चार अन्य सहयोगी भी संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। अभियुक्त नीरज कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस टीम द्वारा जब्त सामानों में एक लैपटॉप, सात मोबाइल, पांच एटीएम कार्ड, चार सिम कार्ड, चार पासबुक और एक चेकबुक है। नीरज कुमार अभियुक्त जिला-नालंदा निवासी है। वह हिलसा थाना का रहने वाला है। पाटना साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्रधारिया के नेतृत्व में धर्मेन्द्र मंडल, अरविंद कुमार, अमर कुमार, सभी पटना साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाकर सभी साइबर ठगों को दबोचा है। पटना साइबर थाना के डीएसपी नीतीश चंद्रधारिया ने सारे साइबर कांडो का खुलासा बहुत किया हैं। वह लोगों से अपील करते हैं कि साइबर ठगों के झांसे में न आएं। सजग एवं सतर्क रहकर एक जागरुक नागरिक बनकर लोगों को जागरूक करें, जिससे वे साइबर अपराधियों के शिकार होने से बचे। अनजान भेजे गये लिंक apk file या KYC के नाम पर ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहें। उन्होंने बताया कि इनका नेटवर्क पूरे देश के अलग-अलग साइबर फ्रॉडस्टर से जुड़ा है। इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई समेत देश के अलग-अलग 40 से अधिक शिकायत एन.सी.आर.पी. की पोर्टल के जरिए मिली थी। अभी तक जाँच में अलग-अलग खाते से लगभग 2 करोड़ से भी अधिक के ट्रांजेक्शन मिले हैं।●

पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार का जवाब
40 बेडों के अस्पतालों के लिए समिति बना रही दिशा-निर्देश

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

बिहार राज्य में 40 बेड तक वाले अस्पतालों के विनियमन से जुड़े मामले में पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की। डॉ. दिलीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत जानकारी पेश की। माननीय न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या-480 (18), 04 मार्च 2025 के माध्यम से बिहार

क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है। इसके तहत एक से 40 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को फिलहाल नियमों से अस्थायी छूट दी गयी है। संशोधन के बाद कई जिलों के सिविल सर्जनों ने इनके नियंत्रण और नवीकरण संबंधी दिशा निर्देशों पर स्पष्टता मांगी थी। इस पर स्वास्थ्य विभाता स्पष्टता ने छह सदस्यीय समिति बनायी है। जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देशक प्रमुख डॉ. प्रमोद कुमार सिंह कर रहे हैं। समिति नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रही है।●

तारेगना में आर्यभट्ट की वेदशाला बनाने की मांग

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

दिनांक 17 नवंबर 2025 को बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी को आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से तारेगना में वेधशाला बनाने के लिए ज्ञापन दिए तारेगना स्टेशन पर भव्य मूर्ति एवं जीवनी लिखा जाए आर्यभट्ट का बिहार के महामहिम खान साहब बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है आश्वासन दिए जरूर बनेगा हम लोगों को काफी समय भी दिए और इनके विचार और व्यवहार से काफी हम लोग प्रभावित हुए तारेगना के किसानों को सततलीज पर जो जमीन दिया गया है वेधशाला बनाने के लिए इसका भी पैसा दिलाने के लिए आश्वासन दिए आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय से मांग किया कि यथाशीघ्र वेधशाला बनाया जाए स्टेशन पर भव्य मूर्ति का निर्माण हो तथा आर्यभट्ट की जीवनी लिखा जाए इससे पर्यटक लोग मसौढ़ी में काफी लोग आएंगे ज्ञापन देने वाले में आर्यभट्ट चेतना मंच राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना पासवान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह मुखिया चंदन भारती पटना जिला महासचिव महानंद यादव जी ज्ञापन सौंप कर आग्रह किया जल्द से जल्द बनाने का कृपा किया जाए आर्यभट्ट के वेधशाला बनाने के लिए काफी उत्सुक थे हमारे महामहिम बिहार के अगर वेधशाला बनता है पर्यटक लोग काफी मात्रा में मसौढ़ी आएंगे पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी आएंगे बोधगया से भी ज्यादा तरेगनामें आएंगे इसलिए की वैज्ञानिक पूरे विश्व में होते हैं धार्मिक संस्था नहीं है आर्यभट्ट गणितज्ञ थे वैज्ञानिक थे खगोलविद थे दार्शनिक थे ऐसे महान विभूति के नाम पर वेधशाला बनेगा बिहार राज्य का विकास होगा पर्यटक आएंगे और पर्यटक से जो पैसा हमारे बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा इसलिए महामहिम से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द वेधशाला बनाया जाए। ●

कैंसर रोग से ग्रसित लोगो का मसौढ़ी में इलाज संभव

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

राजधानी पटना से लगभग 30 किमी. की दूरी पर मसौढ़ी में अब मेडिमातृत्व एवं सर्जरी क्लिनिक में कैंसर सर्जन, स्त्री एवं प्रभूति रोग विशेषज्ञ, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ और न्यूरो साइकेट्रिस्ट उपलब्ध हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग रोगों का इलाज होता है। शरीर से कैंसरयुक्त ट्यूमर को हटाने के लिए अब बड़े-बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। मसौढ़ी के लोगों को मसौदी में ही यह सुविधा मिल रही है। मसौढ़ी के हनुमान नगर बिरंची रोड स्थित रामावतार मार्केट में मेडिमातृत्व एवं सर्जरी क्लिनिक अस्पताल में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। यहाँ पर डॉ०पी० कुमार जेनरल एवं कैंसर सर्जन, डॉ. श्वेता सिन्हा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, स्त्री एवं बच्चेदानी से संबंधित बीमारी का इलाज करेगें। डॉ० पी० कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि शरीर के विभिन्न गाठ का इलाज, पित्त की थैली, पथरी, बबासीर हर्निया,

हाइड्रोसील का समुचित इलाज किया जा रहा है। यहाँ दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। डॉ. पी. कुमार लोक नायक हॉस्पीटल नई दिल्ली में सिनियर रेसिडेंट रहे हैं एवं महावीर कैंसर संस्थान, पटना में अपनी सेवा दे चुके हैं। डॉ. सुप्रिया कुमारी न्यूरो साइकेट्रिस्ट जो अपनी सेवा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पीटल नई दिल्ली में दे चुकी हैं। वह मनोरोग से संबंधित बीमारियों का इलाज करती हैं। इस मौके पर डॉ० अखिल पीयूष, वरिष्ठ चिकित्सक पी.एम.सी.एच. पटना भी मौजूद रहे। सभी डॉक्टरों ने जनजागरुकता अभियान चलाकर रोगों इलाज किया। डॉ. सुप्रिया कुमारी ने मनोरोग से संबंधित बीमारी पर चर्चा की। वह बतायी कि अगर बच्चा ADHD, ऑटिज्म, कमजोर बुद्धि, देर से बोलना, हकलाना, पढाई में कमजोर, व्यवहार परिवर्तन, जिद्दीपन या चिड़चिड़ापन, तोड़-फोड़ करना, बार-बार बेहोश होना या मिर्गी जैसा लक्षण, सिर दर्द, अधिक चंचलता और रात में बिस्तर गिला करना आदि रोगों से ग्रसित है तब नि:संकोच यहाँ रोगियों को लाया जाए। यहाँ उनका समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सभी डॉक्टरों ने दर्जनों मरीजों का नि:शुल्क इलाज करके अपने सेवा धर्म को बखूबी निभाया। ●

फतुहा विधानसभा का रूप बदलने का सपना
रुपा का रह गया सपना

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा नगर परिषद के अध्यक्ष रुपा कुमारी का सपना था फतुहा नगर के सुरत बदलने का? रुपा कुमारी ने फतुहा का सुरत बदल दिया। फतुहा का सुरत देखने लायक कर दिया। यह सचमुच में रुपा का कमाल कर दिया। स्टेशन स्टेशन रोड में अस्पताल के समीप शौचालय निर्माण कर दिया । महारानी चौक के पास एक अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण, 16 हाई मास्क लाइटों की स्थापना, पांच एलइडी टीवी स्क्रीन, 5 आई लव फतुहा बोर्ड का इंस्टालेशन और रेलवे कॉलोनी में तीन विभिन्न स्थानों पर पीसीसी सड़क एवं नाला का निर्माण शामिल है। इन परिणामों को पूर्ण करने में 16 है मास्टर लाइटों पर एक करोड़ 20 लाख रुपए, पांच एलईडी स्क्रीन पर 7 लाख रुपए ,पांच आई लव पटना बोर्ड पर पांच लाख रुपये।शौचालय निर्माण पर 9 लाख रुपए और 3 पीसीसी सड़क व निर्माण पर 45 लख रुपए खर्च किए गए हैं। इन सभी योजनाओं का कुल योग लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हैं जिसका विद्धिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य पार्षद रूपा कुमारी ने कहा कि हमारा एक और लक्ष्य है कि जिस प्रकार फतुहा शहर का सूरत बदल दिया उसी प्रकार फतुहा

विधानसभा क्षेत्र का भी सूरत बदल दें। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि पहली बार विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आकर 80 हजार से भी जयादा वोट मिलना भारी जीत ही माना जाएगा। बताया जाता है कि जिस प्रकार भाजपा के लोगों को सहयोग करना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिला। चुनाव के पहले भाजपा एक बैठक में अमृता भुषण राठौर ने डांटते हुए कहा कि तुम लोग भाजपा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा में एक जुट रहता तो भाजपा को हार का मुहं नहीं देखना पड़ता। रुपा बधाई का पात्र है कि पहली बार फतुहा में महिला का सीट लेकर चुनाव क्षेत्र में आई थी।●

बिहार के भाजपाइयों ने भाजपा की छवि को पूरी तरह धूमिल कर दिया है

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार में 20 साल के लगभग सत्ता में रहने के बावजूद बिहार में एक भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय या आदित्यनाथ योगी पैदा नहीं हुआ तथा भाजपा का सिद्धांत नहीं सीख पाया। बताया जाता है कि शाम को भाजपा में आया तथा सुबह में चुनाव के लिए टिकट मिल गया, दूसरीओर लमबे समय से भाजपा का दरी उठाने और बिछाने वाला दरी बिछाने वाला ही रह गया। बड़े-बड़े पद पर बैठने वाला शायद यह भी नहीं जानता है कि हम किसे वोट दें यह जानने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पौलिटकल पुस्तक को पढ़ना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन

में कहा था भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है, सबों को आगे आना होगा, मतलब भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा इसके लिए मोदी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताएं रास्ता पर चलना होगा। अब तो देखते हैं कि ठेकेदार भी भाजपा में है जबकि ठेकेदारी और ईमानदारी साथ-साथ नहीं चल सकता है । अपराध और भ्रष्टाचार के बिहार के भाजपाई कभी भी मुंह नहीं खोला। भाजपाई के लिए भ्रष्टाचार अपराध का विरोध उनके लिए अपनी सरकार का विरोध माना जाता है जब सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार और अपराध को नियंत्रित करना संभव नहीं है तो फिर सरकार और सत्ता से बाहर रहकर क्या यह संभव है।●

देश के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट से एक साथ माफी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

देश की न्याय की इतिहास में एक चौका देने वाला पन्ना जुड़ गया। दो राज्यों पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर देश के तमाम सूबों के मुख्य सचिवों को सर्वोच्च न्यायालय से एक साथ माफी मांगनी पड़ी। दरअसल 22 अगस्त को ही शीर्ष अदालत ने देश भर के नगर निगमन को यह आदेश जारी किया था कि वह पशु जन्म नियंत्रण के नियमों के अनुपालन के लिए जरूरी संसाधनों मसलन लावारिस कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारियों विशेष वाहनों पशु चिकित्सकों और कुत्तों से जुड़ी जानकारी विस्तार से दें, मगर 27 अक्टूबर को जब तीन जजों के बीच मामले की आगे सुनवाई के लिए बैठी तो सिर्फ दो राज्यों का हलफनामा उसके सामने था, ऐसे में स्वाभाविक ही सख्त रूप अपनाते हुए पीठ ने बाकी सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को तलब कर लिया। जाहिर है, सभी राज्य प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ और सोमवार को उनका मुख्य सचिवों के माफी नामा के साथ अपेक्षित हेल्पनामा भी दायर करना पड़ा। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी शुक्रवार को होगी। यह पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमारे तंत्र की दशा से उदासीनता का एक ताजा उदाहरण है इससे यही जाहिर

हुआ है कि जब आला अधिकारियों को अपने किसी आदेश के अनुपालन के लिए कठोर कदम उठाने का वाध्य होना पड़ रहा है तो जिला अदालत के आदेश के पालन में कितनी ही लापरवाही होती होगी यह न सिर्फ न्याय एक पालिका के लिए बल्कि कार्यपालिका के लिए भी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। लावारिस कुत्तों के काटने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ बच्चों में रेबीज होने की खबर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला शुरू किया था। बाद में इसे राष्ट्रव्यापी समस्या मानते हुए इसका विस्तार देश के स्तर पर कर दिया। यकीनन इससे अदालत की संवेदनशीलता का पता चलता है। मगर हमारा प्रशासनिक अमला नागरिकों के प्रति अपना एक जरूरी दायित्व निभाने में सफल रहा और अदालती सक्रियता की बावजूद लापरवाही की चादर ओढ़ रहा। सवाल है कि अधिकारियों में यह दु साहस आ काहाँ से रहा है। जब दुनिया भर में रेवीज के कारण मरने वाले लोगों में से 36 प्रतिशत भारतीय हैं। मुख्य सचिवों के लिए यह सोंचने का समय है। हमारी अदालतों में लाखों मुकदमे लंबे खिंचे जाने का एक बड़ी वजह है वक्त काटने की यह प्रशासनिक सस्ती है। अदालतें वेहद गंभीर अपराध के दोषी को बिना शर्त माफी माग लेने पर छोड़ती रहेगी तो दूसरे अफसरों में आदालती आदेश की अवहेलना के दंडनीय होने का भय भला कैसे रहेगी। न्याय के राज की पहली शर्त है न्यापालिका का सम्मान अक्षुण्ण रहे।●

नीतिन नवीन भाजपा में रहकर भी संस्कार नहीं सीखा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

नीतिन नवीन भाजपा में रहकर भी संस्कार नहीं सीखा। भाजपा की सबसे बड़ी भूल थी की नीतिन नवीन को सुंदर चेहरा देखकर शायद मंत्री का मुकुट पहना दिया गया। राम मनोहर ने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर से अन्याय के प्रति ज्वाला धधक रहा हो वैसे व्यक्ति से अच्छी भाषा की आशा न करे। नितिन नवीन नवीन चेहरा चमका कर भाजपा में प्रवेश कर गया। अंग्रेज के समय 1884 में निर्माण किया गया लोहा का पुल प्रशासन की लापरवाही से 20 मई 2021 को ही टूट गया। टुटा हुआ पुल निर्माण के कौन कहे नीतिन नवीन आज तक देखने भी नहीं आया। यह पुल निर्माण के लिए अथक प्रयास कर पुर्व पार्षद केशर प्रसाद ने पुल पास करवा दिया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद में चले गए

उसके बाद यह पुलष का उद्घाटन विधायक रामानंद यादव ने किया था। उसके बाद नीतीश कुमार फिर भाजपा में आ गए। पुल अधुरा वैसे ही है। पुल के लिए धरणा भी दिया गया। पुल अभी भी अधुरा है। यह मात्र पुल ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी है। इस पुल से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि फतुहा के क्रांतिकारी ने दो अंग्रेजों को फतुहा रेलवे स्टेशन से खींचकर तथा रस्सी से बांधकर एक टमटम पर लाद कर जीवित अवस्था में ही इसी पुल के पानी में डाल दिया गया था । यह एक अंतरराष्ट्रीय घटना थी। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार फतुहा रेलवे उतरकर इसी पुल से पटना गए थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति ने प्रथम आकर इसी पुल से पटना गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद फतुहा आए थे तो इसी पुल से गए थे। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण हाई स्कूल में आए थे तो इसी पुल से गुजरे थे।●

हुंकार रैली में घायल जितेंद्र मिस्त्री उपेक्षा के शिकार

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले पटना गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में कई बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी तथा कई घायल हुए थे। संयोग था कि प्रधानमंत्री के सबसे निकट वाली बम नहीं ब्लास्ट हो सका था अन्यथा बहुत बड़ी अनहोनी प्रधानमंत्री के साथ हो सकती थी। ईसी बम ब्लास्ट में फतुहा के जितेंद्र मिस्त्री भी घायल हुए थे। घायल होने के बावजूद भी भाजपा और मोदी के पक्ष में उत्साह के साथ पहले की तरह लग रहे। फतुहा भाजपा के कर्ण धार को चाहिए था कि बाहर से आए अतिथि को एक बार घायल जितेंद्र मिस्त्री को भेंट करवा देना। मुख्य अतिथि को भी यादगार रहेगा कि मोदी की हुंकार रैली में घायल भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र मिस्त्री से मुलाकात करने का मौका मिला तथा अपने आप को धन्य महसूस करते। जब भी बाहर के अतिथि आते तो भाजपा के एक -एक कार्यकर्ता अपने आप को गर्व महसूस करते। स्थानीय सांसद रवि शंकर प्रसाद भी कभी मुलाकात नहीं कर पाए मुलाकात नहीं करने के पीछे क्या कारण है वही बता सकते हैं। नहीं आने के पीछे जातिया कमाने खाने वाला साधारण व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा के नेताओं के मन में किसी तरह का प्रेम नहीं होता। बस उपयोग करो? ●

बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए होमियोपैथी दवा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉ० गोपाल प्रसाद ने संचालन किया। स्वास्थ्य शिविर के इस आयोजन में पूजा कुमारी के साथ ही तथा अन्य लोग शामिल हुए एवं मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध होमियोपैथी चिकित्सक डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल मौजूद रहे। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए उसके वेशभूषा, चाल ढाल के साथ उसे बोलचाल अच्छा नहीं है तो उसके स्वास्थ्य, आकर्षक, व्यक्तित्व का असर कम होने लगता है। केवल पुरुष ही नहीं आज के तो स्त्रियां भी नशे की आदत की शिकार होती जा रही है। इससे उनके सौंदर्य में अनावश्यक व्यवधान आने लग जाता है । जैसे बार-बार पान या तंबाकू खाते रहना, शराब भांग, गांजा ,बीड़ी सिगरेट पीते रहना आदि। इसलिए ऐसे व्यसनों से यथा संभव बचाए रखें।

शराबी व्यक्ति का समाज में परिवार में, कोई सम्मान नहीं रहता, कितना भी सुंदर वह आकर्षक क्यों न हो सम्मान नहीं मिलता है। यदि शराब पीने का आदी बन चुका है तो लोग उसके संपर्क से बचने का ही प्रयास करते हैं। शराबी व्यक्ति को एक बूंद नित्य दिन एक बार लेने

से शराब छुड़ाने के लिए होमियोपैथी दवा सल्फर 200 एक बूंद नित्य दिन लेने से कुछ समय में पीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। दूसरा दवा सिफिलिनम 200 इस दवा भी एक बूंद नित्य दिन लेने से शराब पीने से कुछ दिनों में शराब पीने की आदत समाप्त हो जाती है।

आपका बच्चा अगर रात को रोता है और दिन में सोता है तो ऐसे अवस्था में होमियोपैथी दवा कैमोमिला 30 कुछ ही खुराक ही खुराक काफी है। बचों को अगुंठा चुसने का आदत दवा नेट्रम म्यूर 1 एम कुछ ही दिनों में आदत छूट जाती है। बच्चों का देर से चलना, बोलना सीखाने के लिए दवा कैलकेरिया कार्व 30 यह दिमाग को भी तेज करता है। बच्चा गोद में घुमने के लिए जिद् करने पर दवा एन्टीरोमिनियम टार्ट 30 कुछ ही दिनों में आदत छूट जाती है। बच्चा हकलाना, तोतलानाना दवा स्ट्रोममोनियम 30, बोविस्टा 30, कैनाबिस इंडिका 30 कोई भी एक दवा का इस्तेमाल करें।जीभ मोटा होने के कारण हकलाना जेलिसीमिय 30 एक बूंद तीन बार रोज। कमजोर दिमाग के बचा को इथूजा 30,200।

कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से इस्तेमाल करें। इस अवसर पर अनील कुमार शर्मा, सीमा कुमारी, शोभा, ममता पटेल, मनोरमा कुमारी, मनीषा, कुमारी, रवि प्रकाश शामिल रहे। ●

पहली बार महिला प्राचार्या बनी प्रो. (डॉ.) कंचन गुप्ता

● प्रो० रामजीवन साहु

भारत को लाखों क्रान्तिकारियों के बलिदानियों के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आधी रात में स्वतंत्रता प्राप्त हुई. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरे जमुई अनुमंडल में सर्वप्रथम जमुई नगर में 1955 में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु कुमार कालिका मेमोरियल महाविद्यालय की स्थापना हुई. आगे चलकर यह के0 के0 एम0 कालेज के नाम से प्रसिद्द हुआ. कुमार कालिका तात्कालीन गिद्धौर महाराजा के चाचा थे. ये एक कुशल समाज सेवक और उच्च शिक्षा के प्रसार में गहन रूचि रखते थे. इसी कारण उनके नाम पर कालेज का नामाकरण हुआ. 70 वर्षों बाद के0 के0 एम0 कालेज, जमुई को 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार को प्रो0 (डॉ0) कंचन गुप्ता प्रोफेसर प्राचार्या के रूप में अपना योगदान दीं. वे पहली महिला प्राचार्या भी बनीं. कंचन गुप्ता बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग-2025 के द्वारा चयनित हुई हैं.

कंचन का शाब्दिक अर्थ मुख्य रूप से सोना और पवित्र होता है ,परन्तु कंचन शब्द के प्रत्येक अक्षर भी कंचन के विशेषताओं का उल्लेख प्रस्तुत करता है. क+न+च +न = कंचन. क से कर्मनिष्ठ ,न से न्यायप्रिय, च से चतुर और न से नम्र अर्थात जो कर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय ,चतुर

और नम्र हो वही कंचन कहलाता है.

☞ **परिस्थिति :-** सामाजिक परिस्थिति को देखकर इनकी माता -पिता सिर्फ यही चाहते थे कि मेरी लाडली पुत्री को चिट्ठी -पत्री पढ़ने -लिखने का ज्ञान हो जाये ,लेकिन पुत्री के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में सरस्वतीजी और गणेशजी सोने का सिंहासन लगाकर बैठे हुए थे, इसलिए इन्होने क्रमभंग किये बिना उच्च शिक्षा ग्रहण करना जारी रखीं . वह जानती थीं कि मेरे पूजनीय माता -पिता पैसे के कारण पढ़ाना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने वर्ग और सामाजिक वातावरण के कारण पढ़ाना नहीं चाहते हैं. 2003 में उनके माताजी श्रीमती गुलाईची देवी और पिताजी श्री शिव कुमार गुप्ता का खुशी का ठिकाना नहीं था ,जब सुना कि मेरी प्यारी बेटी व्याख्यता बन गयी है.

☞ **कर्मभूमि :-** पांच जून 2003 को बी0 आर0 एम0 कालेज, पूरबसराय, बासुदेवपुर, मुंगेर की व्याख्यता बनी. उस समय यह कालेज तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर में था.

☞ **विवाह संस्कार :-** 22 नवम्बर 2004 में ये सामाजिक बंधन यानि इनका विवाह श्रीमान् किशोरी साव के साथ हुई. ये उस समय आई0 ई0 मिनिस्टरी आफ डिफेन्स में जुनियर डायरेक्टर थे. इनका पैतृक गांव बोड़ना है, जो लखीसराय जिला में है.

☞ **उन्नति :-** 27 मई 2021 में ये बी0 आर0 एम0 कालेज का उपाचार्य बन गयी ,अब यह कालेज मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर में आ गया.

☞ **विशेष रूचि :-** इनकी विशेष रूचि स्वाध्याय, अध्यापन और लेखन में है. अभी तक इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-आधुनिक भारतीय दर्शन को स्वामी विवेकानंद का अवदान एक समीक्षात्मक अध्यन (2018) और भारतीय दर्शन में पर्यावरण विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र, अनेक राष्ट्रीय -अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार (2018). ●

प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार को दी गई भावभीनी विदाई

● मो० सईद

थाना परिसर शेरघाटी 28 नवंबर को आयोजित समारोह में प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार को विभागीय कर्मियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने उन्हें शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मात्र दो माह के अल्पकालिक कार्यकाल में अभिषेक कुमार ने पुलिसिंग के महत्वपूर्ण गुर सीखते हुए बेहतर समन्वय स्थापित किया है। एएसपी ने कहा कि जिसने अच्छे से थानेदारी कर ली उसकी पुलिसिंग सफल मानी जाती है। उन्होंने बताया कि योगदान देने के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य सामने आ गए जो किसी भी नए पदाधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने बड़े धैर्य और सूझबूझ के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। प्रभार संभाले नए थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने भी उनके कार्यो की सराहना करते हुए कहा

कि कुमार ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रेम और सहज व्यवहार से कार्य कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस दौरान प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण का हर पल चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि अधिकांश कार्य फोन से ही निपटाने पड़ते थे। उन्होंने कहा प्रशिक्षण के दौरान मुझे भरपूर सहयोग मिला। हर समस्या और हर क्षण साथ खड़े रहने का समर्थन मिला। मेरे पहले ही दिन सामुदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी सीखने की प्रक्रिया जारी है। जितनी तैयारी करता हूं उतना ही अनुभव बढ़ता है। मेरी नीयत हमेशा साफ रखने की कोशिश रही है। नए थानाध्यक्ष को भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेख्र इसी आशा के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के अंत में विभागीय कर्मियों ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रशिक्षु डीएसपी का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन सर्किल इंस्पेक्टर नेयाज अहमद ने किया। जबकि पुलिस अधिकारी राजेश कुमार, भरत यादव, रविराज कुमार, रितेश कुमार, राजकिशोर सिंह आदि मौजूद रहे। ●

बिहार की राजनीति में मगध प्रमंडल का नवादा जिला ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नवादा न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, बल्कि यह राज्य की राजनीति में बाहुबल, धनबल और जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला भी रहा है। जिले के अंतर्गत पांच विधानसभा क्षेत्र आते हैं :- नवादा, वारिसलीगंज, हिसुआ, रजौली (सुरक्षित) और गोबिंदपुर। इन पांचों सीटों का चुनावी इतिहास बिहार की सत्ता के परिवर्तन के साथ-साथ स्थानीय वर्चस्व की कहानियों को भी बयां करता है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों (2025) के परिणाम नवादा जिले के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक और चौंकाने वाले रहे हैं। इन परिणामों ने न केवल पुराने गढ़ों को ध्वस्त किया है बल्कि नए राजनीतिक समीकरणों के उदय का भी संकेत दिया है। 2025 के जनादेश की सबसे बड़ी विशेषता 'महिला शक्ति' का अभूतपूर्व प्रदर्शन रही है। नवादा जिले की 5 में से 3 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो नवादा जिला परंपरागत रूप से भूमिहार और यादव जातियों के वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। हालांकि, इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरह से दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों को साधा, उसने जिले की राजनीति की दिशा बदल दी है। एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा (रामविलास) ने रजौली और गोबिंदपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर कब्जा जमाया, जो पहले आरजेडी या कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र माने जाते थे।नवादा विधानसभा सीट, जो जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां सत्ता का एक दिलचस्प परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ राजबल्लभ यादव और उनके परिवार का दबदबा दशकों से रहा है। उनकी पत्नी विभा देवी, जो 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीती थीं, 2025 में जेडीयू के तीर के साथ मैदान में उतरीं और जीत हासिल की। यह जीत व्यक्तिगत रसूख और दलबदल की राजनीति के सफल प्रयोग का उदाहरण बनी। दूसरी ओर वारिसलीगंज में एक बड़ा उलटफेर हुआ। यहां भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता अरुणा देवी, जो पिछले कई चुनावों से अजेय मानी जा रही थीं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी की अनीता देवी ने उन्हें हराकर इस सीट पर 'लालटेन' जलाया। यह परिणाम दर्शाता है कि जनता अब लंबे समय से काबिज चेहरों के खिलाफ भी जाने में संकोच नहीं कर रही है।हिसुआ में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां कांग्रेस की नीतू कुमारी अपनी सीट नहीं बचा सकीं और बीजेपी के अनिल सिंह ने जोरदार वापसी करते हुए फिर से 'कमल' खिलाया। हिसुआ का परिणाम कांग्रेस के लिए मगध क्षेत्र में एक बड़ा झटका साबित हुआ।कुल मिलाकर, नवादा के इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम बताते हैं कि मतदाता अब केवल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, स्थानीय समीकरण और विकास के मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लोजपा (आर) का उदय और महिलाओं की भारी जीत ने नवादा को बिहार की राजनीति में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नवादा जिले की पांच सीटों पर कैसा परिणाम रहा, पर प्रस्तुत है सहायक संपादक **मिथिलेश कुमार** के साथ केवल सच टीम की चुनावी रिपोर्ट :-

गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र, संघर्ष से सफलता तक
विनिता मेहता की जीत की कहानी : संघर्ष, सामाजिक जुड़ाव और बदलते जनमत का दस्तावेज :-

नवनिर्वाचित विधायक विनिता मेहता का जिला परिषद सदस्य से बिहार विधान सभा सदस्य तक संघर्ष पूर्ण यात्रा सामाजिक जुड़ाव ने मुकाम तक पहुंचाया है। जीवन में सीढ़ियों पर चढने की निरंतर आदत मनुष्य को मंजिल पर पहुंचा देती है। खासकर वैसी परस्थिति में जब आप दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य पर ईमानदारी पूर्वक काम करते रहें। कवि ने क्या खूब कहा है 'लहरों से डर कर नौका पार नही होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।' जब समुद्र में लहरें अपने यौवन पर होती है और नाविक अपने लय में गीत गाते हुये लहरों को पार कर अपने मंजिल तक पहुंचता है। मैं आज बात कर रहा हूँ नवादा जिले के वैसी महिला नेत्री का जिन्होंने

राजनीति में कदम रखा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा रोह प्रखंड से जिला परिषद सदस्य बन कर पहली बार जिला सदन में पहुंचने वाली विनिता मेहता ने पहली बार में ही बिहार विधान सभा का चुनाव जीता और करीब 60 वर्षों के बाद क्षेत्र में कुशवाहा राजनीति का उदय हुआ। खासकर वैसी स्थिति मैं जहाँ एक तरफ वर्षों तक गायत्री देवी से लेकर कौशल यादव परिवार का वर्चस्व रहा, दूसरे तरफ मोहम्मद कामरान का पाँच वर्षो का 'काम का कामरान' जैसी अवधारणा वाली राजनीति के बीच 22 हजार से अधिक मतों से जीत हासिल करना आसान नहीं था, परन्तु विनिता मेहता ने हार नही मानी और बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में जबरदस्त एन्ट्री कर सबों को चौका दिया) हालांकि विनिता मेहता की राजनीतिक विरासत मुख्य रूप से पूर्व जिला परिषद सदस्य सह वर्तमान में भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता से मिला हुआ है जो इनके पति है। नवादा की राजनीति में लंबे अर्से से स्थापित अनिल मेहता ने बीते लोक सभा चुनाव में पार्टी का वफादार सिपाही बनकर हमेशा अपने कर्तव्यों पर अडिग होकर विवेक ठाकुर को सांसद बनाने में अहम भूमिका निभाया। और ईनाम में गोविन्दपुर विधानसभा सीट प्राप्त किया। वैसे तो 2025 का विधान सभा चुनाव की बात करें तो एनडीए की सुनामी थी जिसमें कई विधायकों ने जीत हासिल किया लेकिन गोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र में विनिता मेहता का अपना मेहनत ही सफलता, दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि पिछले चार बर्षो से कमोवेश पुरे माह तक क्षेत्र में किसी न किसी बहाने लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक की शादी विवाह, छठी, श्राद्ध, जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के कारण महिलाओं और ग्रामीण लोगों के बीच चहेती बनकर रही। वहीं मुख्यमंत्री का जीविका दीदियों को दस हजार रुपये का गिफ्ट और असरदार रहा नतीजा विनीता मेहता ने राजद का किला ध्वस्त कर एनडीए को जीत दिलाने में सफल रही।

☞ **गोविन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में 60 वर्षो के बाद बदला राजनीति का मिजाज :-** राजनीति में विरासत से ज्यादा मूल्य मेहनत, निरंतरता और जनसंपर्क का माना जाता है। लेकिन गोविन्दपुर विधानसभा ने इस बार यह साबित भी कर दिया कि यदि नेतृत्व में सादगी, पहुंच और भरोसा हो, तो दशकों पुरानी राजनीतिक धारणाएँ भी ध्वस्त होती हैं। इसी पृष्ठभूमि में नवनिर्वाचित विधायक विनिता मेहता की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि क्षेत्र में उभरते नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। जिला परिषद सदस्य से विधायक तक संघर्ष और सीढ़ियों का सफर में विनिता मेहता ने राजनीति की शुरुआत रोह प्रखंड से जिला परिषद सदस्य के रूप में की थी। पहली ही बार में जिला परिषद की कुर्सी पर बैठना और फिर क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना यह उनकी लोकधर्मी शैली की पहचान बन गया। यह वही समय था जब स्थानीय राजनीति में लोग उन्हें 'सुनने वाली' नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचानने लगे। शादी-विवाह, जन्मदिन-श्राद्ध आदि छोटे छोटे कार्यक्रमों में सामाजिक जुड़ाव के साथ महिलाओं के मुद्दों पर लगातार संवाद भी करती रही। इन सबने उन्हें गाँव-गाँव तक एक भावनात्मक पहचान दी। अगर हम राजनीतिक विरासत की बात करें तो सफलता सिर्फ विरासत की नहीं निस्संदेह, उनकी राजनीति की बुनियाद भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल मेहता की लंबे समय से चली आ रही संगठनात्मक हैसियत से मजबूत हुई। अनिल मेहता पार्टी के वफादार सिपाही, लोकसभा चुनाव में विवेक ठाकुर को जिताने में अहम भूमिका, और वर्षों की नेतृत्व क्षमता इन सबका लाभ विनिता मेहता को मिला। लेकिन चुनाव में यही काफी नहीं था। जिस तरह उन्होंने चार वर्षो तक लगातार क्षेत्र में उपस्थित रहकर, निजी संबंधों को राजनीतिक ताकत में बदला, वही उनकी जीत का निर्णायक कारक भी बना। पुराने विधायकों का वर्चस्व में गोविन्दपुर सीट दशकों तक दो ध्रुवों के इर्द-गिर्द घूमती रही थी। गायत्री देवी और कौशल यादव परिवार का पारंपरिक प्रभाव विधानसभा में रहा।

मोहम्मद कामरान का उभरता हुआ 'काम का कामरान' वाला मॉडल भी प्रभावी था। पिछले चुनाव में कामरान की छवि विकास और संगठनात्मक सक्रियता की वजह से चर्चित थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। हार के प्रमुख कारण पिछले पाँच वर्षो में कुछ बड़े वादों पर जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। गाँवों में संपर्क सीमित हुआ, खासकर महिला समूहों और युवा मतदाताओं में। जातीय और सामाजिक गोलबंदी इस बार उतनी कारगर नहीं रही। एनडीए की प्रदेश भर में चली 'सुनामी लहर' का स्थानीय असर भी कहा जा सकता है। जीत से ज्यादा बदलाव का संकेत भी है। करीब 22 हजार से अधिक मतों से मिली जीत इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है इन्होंने पूर्णिमा यादव को भारी मतों से हराया है। इससे पहले लगभग 60 वर्षों तक कुशवाहा समाज की सीधी भागीदारी सत्ता में नहीं दिखी। इस चुनाव ने उस लंबे सामाजिक इंतजार की परतें खोलीं। कुछ नीतियों और योजनाओं का असर भी हुआ है। राज्य सरकार द्वारा चुनाव पूर्व शुरू की गई कई योजनाओं ने भी निर्णायक योगदान दिया विशेषकर जीविका दीदी योजना के तहत 10 हजार रुपये, मजदूर परिवारों को राहत राशि, बिजली बिल में कटौती, पीएम/सीएम आवास योजनाओं की तेज रफ्तार, महिलाओं और युवा समूहों पर विशेष ध्यान। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं ने महिला मतदाताओं को बड़े पैमाने पर एनडीए की ओर झुकाया। गोबिन्दपुर विधानसभा की बुनियादी चुनौतियाँ भी रही है जहाँ नई विधायक की परीक्षा भी होगी। अगर माने तो विनिता मेहता की यह जीत जितनी चमकदार है, चुनौतियाँ उतनी ही बड़ी। क्षेत्र में आज भी कई बुनियादी मुद्दे अधूरे हैं। सड़क और संपर्क मार्ग की बात करें तो गोबिन्दपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रखंडो में कौआकोल एवं

गोविंदपुर तथा रोह प्रखंड के कई पंचायतों में अब भी जर्जर सड़कें यातायात और बाजार तक पहुंच कठिन है। हालांकि हाल के दिनों में कामरान के द्वारा किये गए विकास को नजर अंदाज नही किया जा सकता है। जैसा की ककोलत जल प्रपात का विकास, पावर सब स्टेशन सहित कई उल्लेखनीय कार्य किये गए हैं जो करीब चार दशक के बाद हो पाया है।

शिक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, भवन और सुविधाओं का अभाव बड़ी चिंता का बिषय भी हैं। सरकार ने शिक्षकों की बहाली का रिकार्ड भी तोड़ा है लेकिन आज भी कई विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में बिषयवार शिक्षकों की काफी कमी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और उपकरणों की किल्लत अभी तक दूर नही हो पाई है। अस्पताल तक पहुँचने में ग्रामीणों को लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के काफी दुरी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी भी होती है।

सिंचाई और कृषि विकास में नहरें और लघु जल संसाधन परियोजनाएँ अधूरी है। कौआकोल, गोविंदपुर एवं रोह प्रखंड में बर्षा आधारित किसानों को वर्षापरक खेती का जोखिम झेलना पड़ता है। कृषि रोड मैप या अपर सकरी जलाशय योजना का अधर में लटकना और नाटा नदी या अन्य जलाषयों में वियर बांध का न होना भी कृषि को प्रभावित करती है। युवाओं के लिए क्षेत्र में रोजगार के अवसर की भी कमी है। युवाओं में बढ़ती पलायन प्रवृत्ति स्थानीय स्वरोजगार मॉडल पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसे में उम्मीदों का नया अध्याय विनिता मेहता को जनता ने जिस भरोसे से चुना है, वह सिर्फ राजनीति की जीत नहीं यह समाज में

परिवर्तन की इच्छा का जनादेश है। अब इन्हें जनसंपर्क की अपनी पहचान को और मजबूत करना और निरंतर लोगों के सुख दु:ख में शामिल होना इन्हें लम्बे समय तक जोड़ सकता है। बुनियादी विकास पर समयबद्ध काम करके जनता के भरोसे को स्थायी बनाना भी होगा। अगर उन्होंने संगठन, जनता और प्रशासन के बीच समन्वय को जारी रखा, तो गोविन्दपुर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि विकास के नए मानक भी स्थापित कर सकता है। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा राजनीति का उदय हुआ है और इसका श्रेय भी विनीता मेहता को जाता है। विनीता मेहता भी आने वाले समय में समाज और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में निश्चित तौर पर सफल होगी ऐसा मेरा मानना है।विनीता मेहता गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं और उम्मीद हैं की बिना भेद भाव के अपने स्वभाव के अनुकूल अपने पथ पर निरंतर गतिमान रहेगी।

-: रजौली विधानसभा चुनाव 2025 :-
दलगत समीकरण, सामाजिक संरचना और स्थानीय मुद्दों के बीच निकला करीबी जनादेश

नवादा जिले के रजौली (SC) विधानसभा क्षेत्र ने वर्ष 2025 में बिहार की चुनावी राजनीति को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि लोकतंत्र में परिणाम सिर्फ लहरों से नहीं, बल्कि जमीनी समीकरणों से तय होते हैं। यहां का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक संरचना, दलगत प्रतिबद्धताओं और प्रत्याशी की साख इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से संचालित हुआ। इसी के चलते मुकाबला इतना संघर्षपूर्ण हो गया कि अंतत: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विमल राजवंशी मामूली अंतर से विजयी हुए, जबकि राजद की प्रत्याशी पिंकी चौधरी अंत तक कांटे की टक्कर देती रहीं। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं था, बल्कि उस बदलते ग्रामीण-राजनीतिक मानस का संकेत था, जो जाति के ऊपर काम को और वादों के ऊपर विश्वसनीयता को तरजीह देने लगा है।

☞ **जातीय-सामाजिक समीकरण, मतदान की धुरी :-** रजौली एक अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीट है। यहाँ दलित समुदाय बड़ी संख्या में है और विभिन्न उपजातियों के बीच नेतृत्व-साख निर्णायक बनती है। इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), कोयरी-कुर्मी, मुस्लिम मतदाता और सीमावर्ती झारखंड के प्रभावक्षेत्र से जुड़े समूह भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों में देखा गया कि जाति एक अहम कारक के रूप में मौजूद रहती है, पर इस बार उसकी दिशा प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि और स्थानीय उपस्थिति से ही तय हुई। LJP (R) को दलित वर्ग में पैठ का पारंपरिक लाभ मिला। त्श्रक ने अपने सामाजिक गठबंधन-यादव, मुस्लिम, ईबीसी को सक्रिय किया और भाजपा विरोधी भावना को वोट में बदलने की कोशिश की। किन्तु जातीय झुकाव निर्णायक होते हुए भी पूर्ण रूप से एकतरफा नहीं रहा। स्थानीय मुद्दों पर असंतोष, आधा-अधूरा विकास और सरकारी लाभों की पहुंच ने मतदान निर्णय को अधिक लचीला बनाया। लेकिन रजौली में स्थिति अलग थी। यहाँ लड़ाई दो ध्रुवों के बीच सिमटी रही। भाजपा का प्रभाव यहां सीधे तौर पर कम रहा, हालांकि एनडीए के प्रति सकारात्मक रुझान ने LJP (R) को परोक्ष लाभ पहुंचाया। दूसरी ओर आरजेडी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की, महिला मतदाताओं तक पहुंच मजबूत की और ईवीसी वोटों में सेंध लगाने की रणनीति अपनाई। परिणाम चित्र यह बताता है कि जिले की लहर यहाँ पूरी तरह असरदार नहीं रही। इस सीट पर मतदाता दलों से अधिक 'व्यक्ति और काम' को प्राथमिकता दे रहे थे।

☞ **स्थानीय मुद्दों ने चुनाव का असली मोड़ बनाया :-** रजौली का भौगोलिक चरित्र सड़क-संपर्क से जूझता पहाड़ी क्षेत्र, सीमावर्ती बाजारों पर निर्भरता, माइका/खनन क्षेत्र का रोजगार, इस चुनाव में पूरी तरह प्रमुख मुद्दा बन गया। जनता की अपेक्षाएँ थीं गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, बिजली की नियमित आपूर्ति, सिंचाई केसाधन